20 मार्च, 2025 ★ वर्ष 34, पृष्ठ संख्या 60, अंक 03

राजस्थान सुजस

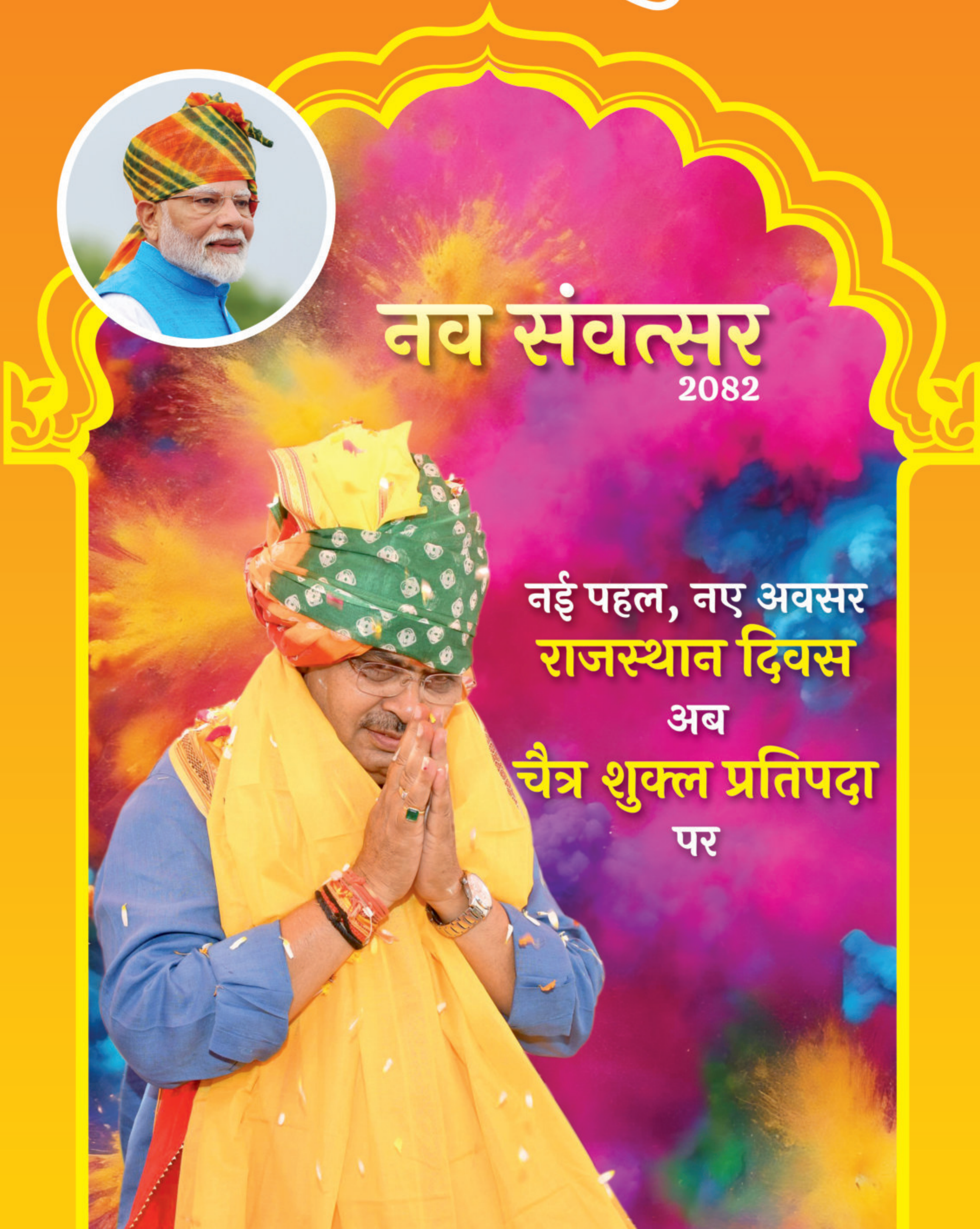

नव संवत्सर 2082

नई पहल, नए अवसर

राजस्थान दिवस

अब

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा

पर

शब्द भावना

> **मैं 'राजस्थान दिवस' भारतीय नववर्ष की शुरुआत पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही मनाए जाने की घोषणा करता हूं।** देश के पहले गृह मंत्री लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च, वर्ष 1949, प्रतिपदा, विक्रम संवत् 2006 के अवसर पर दिए भाषण में हिन्दू नववर्ष पर ही वृहद् राजस्थान की स्थापना को विशेष महत्व दिया था। इस घोषणा से 75 वर्ष बाद राजस्थान दिवस भारतीय रीति-नीति से मनाया जा सकेगा।
>
> 12 मार्च, 2025, राज्य विधान सभा
>
> **- मुख्यमंत्री**

ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक निर्णय

जैसा कि आप सभी को विदित है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत् 2006, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। इसी तिथि को हिन्दू नववर्ष भी मनाया जाता है। नव संवत्सर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक महत्व रखता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। यह दिन महान् सम्राट विक्रमादित्य की विजय का प्रतीक भी है। मां दुर्गा के नव आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र का यह पहला दिन होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हम नये भारत एवं नये राजस्थान के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने सरदार पटेल जी की भावना के अनुरूप राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव संवत्सर पर ही मनाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया है।

हमें गर्व है कि श्रीगंगानगर से बांसवाड़ा और जैसलमेर से धौलपुर तक फैला हुआ हमारा प्रदेश, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह भूमि महाराणा प्रताप और महाराज सूरजमल के शौर्य की है, राणा सांगा के संग्राम की है, तेजा जी के तेज की है, गालव ऋषि के तप की है, मीराबाई की भक्ति की है, भगवान देवनारायण के देवत्व की है, पन्नाधाय के त्याग की है, पद्मिनी के जौहर की है, अमृता देवी के बलिदान की है। यह भूमि नरेन्द्र से विवेकानंद की, भामाशाह के दान की, रामदेव के चमत्कार की, भूरिया बाबा की, गिरिराज धरण की और गोविंद देव जी की पवित्र धरती है। इस पावन भूमि के कण-कण में वीर गाथाएं बसी हुई हैं।

हमारा यह राजस्थान विविधताओं का प्रदेश है, तभी तो कहा जाता है-"कोस-कोस पर पाणी बदले, आठ कोस पर वाणी, पग-पग बदले पागड़ी, नित दीखे नई निशांणी, भांत- भांत का रंग छिप्या छै, भांत- भांत की कहांणी, फेर भी एक है राजस्थान, म्हें एक ही राजस्थानी" राजस्थान के स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मंगलकामनाएं प्रेषित करता हूं।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में "विकसित भारत 2047" के संकल्प को पूरा करने में हमारे प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि हम विकसित राजस्थान 2047 के मिशन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हम सभी संकल्प लें, कि हम अपने राजस्थान को समृद्ध और "आपणो अग्रणी राजस्थान" बनाएंगे। विशेष तौर पर, मेरे प्रदेश की युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि इस स्थापना दिवस पर संकल्प लें, कि वे ज्ञान, शक्ति और भक्ति का अर्जन करते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण में अपना योगदान दें।

आइये! हम इस नव वर्ष और राजस्थान दिवस के शुभ अवसर को नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हुए एवं पर्यावरण प्रकृति सम्बद्ध रहते हुए हर्षोल्लास से मनाएं। पुनः आप सभी को नव वर्ष प्रतिपदा एवं राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।

आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

'भारत माता की जय'

'जय जय राजस्थान'

भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

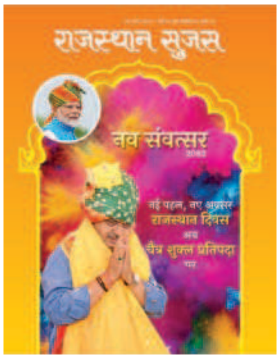

प्रधान संपादक
सुनील शर्मा

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
रवि वर्मा

आवरण छाया
पदम सैनी

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 9587916395
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

ग्राफिक डिजाइनिंग
पॉपुलर प्रिन्टर्स
लागत मूल्य 33.30 रुपये

वर्ष : 34, अंक 03 | मार्च, 2025

इस अंक में

शब्द भावना - ऐतिहासिक दिन...	02
संपादकीय - उत्सव उम्मीदों का...	04
लोक जीवन - गणगौर...	05
महिला सशक्तीकरण...	06
अन्नदाता विकसित, तभी देश-प्रदेश विकसित	08
राज्यस्तरीय अन्त्योदय कल्याण समारोह	10
प्रदेश में रोजगार के अवसर हो रहे सृजित	13
राजस्थान दिवस - भव्य संस्कृति साकार	14
निवेश उत्सव	15
आभार सभा	25
लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व	32
प्रकृति के नन्हे संदेशवाहक	34
50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य	36
आईफा 2025 - जगमगाया राजस्थान...	37
महाकुंभ के पंच महा-अमृत	40
राजस्थान मण्डप	44
होली की उमंग	45
राजस्थान में होगा बुलेट ट्रेन...	48
पंच गौरव- जिलों की पंचमुखी पहचान	50
प्रदेश के विकास में मातृशक्ति...	54
एवीजीसी—एक्सआर नीति...	55
सामयिकी	56
धरोहर - त्रिपुरा सुन्दरी	59

सुशासन का मंत्र... 12

बजट 2025-26 17

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब 26

विश्व वन्यजीव दिवस 28

फूलों की होली... 46

महिला शक्ति के साथ सार्थक संवाद 52

संपादकीय

उत्सव उम्मीदों का...

बसंत से ऊर्जित प्रकृति की लय लिए फाल्गुनी बयार में रच-बस होली का हर्षोल्लास प्रदेश के लोगों के लिए बजट में मिली सौगातों से और बढ़ गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य का स्थापना दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी नवसंवत्सर से मनाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया। अंग्रेजी मानसिकता से मुक्ति और भारतीय संस्कृति से एकात्मकता के लिए यह निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस वर्ष, नव संवत्सर नए संकल्प और नए अवसरों का प्रतीक रहा।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशानुरूप किसान, युवा, महिला एवं गरीब को केन्द्रित रखते हुए राजस्थान दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को अनेक सौगातें दीं।

कृषि में अभिनव प्रयोग, सूरज की ताकत से रोशन भविष्य, युवाओं के हौसले की उड़ान और नारी शक्ति का आत्मविश्वास, सब मिलकर राजस्थान की नई कहानी लिख रहे हैं। इस बार होली के हर रंग में प्रगति की कहानी थी, हर रंग में बदलाव की उम्मीद थी और हर रंग में राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की झलक थी। होली से ठीक एक दिन पहले 12 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के बजट 2025-26 के रूप में खुशियों और विकास के रंगों की गुलाल से सभी राजस्थानवासियों के विश्वास को मजबूती प्रदान की।

सदी की एक बड़ी घटना के रूप में प्रयागराज में एकता का महाकुंभ संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए भी अत्यधिक सराहा गया। साथ ही युवाओं के लिए टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग व पॉलिसी मेकिंग के लिए एक नया अध्ययन क्षेत्र बन गया।

'पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा अन्य जीवों का भी उतना ही अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुरक्षा करें।' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर गुजरात के जामनगर स्थित पशु संरक्षण केंद्र 'वनतारा' का उद्घाटन करते हुए यह संदेश दिया। राजस्थान में पहली बार आइफा अवॉर्ड्स 2025 के आयोजन ने न केवल भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों को राज्य में एकत्रित किया, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अनमोल अवसर भी प्रदान किया।

राजस्थान दिवस के ऐतिहासिक निर्णय और आयोजनों, बजट की सौगातों, फाल्गुन की बयारों, सार्थक संवादों और गहरी संवेदनाओं को समेटे मार्च माह का यह अंक आप सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

(सुनील शर्मा)

प्रधान सम्पादक

राजसी ठाठ से निकली मां गणगौर की सवारी

राजस्थान की शाही परंपरा, लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक गणगौर महोत्सव 2025 इस बार और भी भव्यता के साथ मनाया गया। त्रिपोलिया गेट से राजसी ठाठ के साथ निकली गणगौर माता की सवारी ने समूचे शहर को उत्सवमय बना दिया। देशी-विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ इस ऐतिहासिक सवारी को देखने के लिए उमड़ी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव कर आयोजन की साक्षी बनी।

छाया: राजेंद्र शर्मा

बाड़मेर
राज्यस्तरीय महिला सम्मेलन

महिला सशक्तीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने 25 मार्च को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए अब से राजस्थान दिवस अंग्रेजी कलैण्डर के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (भारतीय नववर्ष) को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान समाज और देश-प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है, इसीलिए राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम मातृशक्ति को समर्पित किया गया है।

आधी आबादी को बड़ी सौगातें

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की चयनित लाभार्थियों से संवाद कर एवं उन्हें योजनान्तर्गत देय सहायता से लाभान्वित किया।

- मुख्यमंत्री ने अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए।
- महिला समूहों को लगभग 100 करोड़ रुपये की आजीविका संवर्धन निधि का हस्तान्तरण और 5 हजार महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप का वितरण किया गया।
- साथ ही, उन्होंने स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत 164 छात्राओं को चयन पत्र का वितरण किया।
- प्रदेश की महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका मेला शुरू किया गया।
- उन्होंने गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन एवं "मुख्यमंत्री हमारी बेटियां" योजना अन्तर्गत 31 हजार 790 बालिकाओं को 13.16 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की।
- विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की बजट घोषणा के क्रम में विभिन्न जिलों के 36 महिला महाविद्यालयों में यह सुविधा प्रारंभ की गई।
- बर्तन बैंक योजना और सोलर दीदी के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए किए अपूर्व निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान कर उनका सशक्तीकरण किया गया है। साथ ही, तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर मुस्लिम बहनों का जीवन भी तबाह होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान संचालित कर, बैंक खाते खुलवाकर, उज्ज्वला सिलेंडर देकर तथा जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव में नल से जल पहुंचाकर प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है।

> "कालीबाई भील, रानी पद्मिनी, मीराबाई, पन्नाधाय और अमृता देवी जैसी महान महिलाओं ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर त्याग और वीरता के अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। परिवार की नींव को मजबूत करने वाली महिलाएं हमारे समाज की भी धुरी हैं। डबल इंजन की राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य कर रही है और आधी आबादी को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है।"

1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 200 करोड़ की राशि हस्तांतरित

श्री शर्मा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सरकार बनते ही सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया। साथ ही, बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई। अब इसके तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड मिलेगा। कार्यक्रम में 30 हजार लाभार्थियों को 7.50 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। कार्यक्रम में 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 200 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया गया।

बालिकाओं को 5 हजार स्कूटियों का वितरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा साथिन बहनों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी भी की है। वहीं अब लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ढ़ाई प्रतिशत के बजाय डेढ़ प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अवसर पर देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 5 हजार स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जल्द शुरू होने जा रहा है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनूं में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के लिए एमओयू हो चुके हैं।

वंचित, महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों के कल्याण को समर्पित बजट

श्री शर्मा ने कहा कि बजट 2025-26 में वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के 'सरस्वती हाफ वे होम्स' के माध्यम से बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष की होने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा भी दी जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि नारी उत्थान के लिए प्रदेश में 10 जिला मुख्यालयों पर 'बालिका देखभाल संस्थान' की स्थापना, नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण, हर ब्लॉक पर रानी लक्ष्मी-बाई केंद्र की स्थापना, जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर बनाकर आगामी वर्ष पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही, राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना प्रारंभ की जा रही है।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा एवं महिलाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से निरंतर भर्तियां आयोजित कर रही हैं। इस बजट में भी सवा लाख भर्तियों की घोषणा की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता के साथ कर रही है और एक साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि महिलाओं के उत्थान के बिना देश और प्रदेश की प्रगति संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने माता बहनों को केंद्र में रखते हुए विकास योजनाएं बनाई हैं।

बीकानेर
किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम

अन्नदाता विकसित, तभी देश-प्रदेश विकसित

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान देश एवं प्रदेश की आत्मा हैं। अगर किसान विकसित होगा, तो देश-प्रदेश विकसित एवं खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सपना सिर्फ 'कृषि विकास' ही नहीं, 'कृषि गौरव' भी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का किसान देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में आदर्श बने। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) से जुड़ें, जिससे वे लाभ की खेती कर खुद को सशक्त बना सकें।

श्री शर्मा 26 मार्च को बीकानेर में राजस्थान दिवस कार्यक्रम शृंखला के तहत आयोजित किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

तपती धूप, कड़ाके की सर्दी, बारिश की बौछार में भी किसान खड़ा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के सम्मान को समर्पित है। किसान सिर्फ खेती नहीं करते, वे जीवन की नींव रखते हैं। किसानों की मेहनत से ही भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है तथा विश्व में हम एक अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सूरज की तपती धूप, कड़ाके की सर्दी तथा बारिश की बौछार में भी खेतों में खड़े रहकर सिंचाई और रखवाली करते हैं। किसानों का यह त्याग और समर्पण अप्रतिम है।

अन्नदाता को मिली अनेक सौगातें

- किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम में 30 हजार किसानों को 137 करोड़ रुपये का अनुदान हस्तान्तरण किया गया।
- इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि में वृद्धि एवं मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।
- मंगला पशु बीमा योजना में लाभान्वितों का दायरा भी बढ़ाया गया।
- पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या बढ़ाकर 200 किए जाने तथा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल से खेती करवाये जाने पर 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- पीएमएफएमई योजना के तीन एफपीओ को अनुदान के तथा एक एफपीओ को शेयर मनी के चैक वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभ की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया

जाए। इसके लिए एफपीओ एक बड़ी पहल है। एफपीओ के माध्यम से किसान सामूहिक होकर काम करते हैं, जिससे उन्हें कृषि अनुदान, सस्ते बीज तथा फसल का उचित मूल्य मिलता है। राज्य सरकार किसानों के हितों का ध्यान रखने के लिए एफपीओ जैसी पहलों को प्रोत्साहित कर रही है।

प्रधानमंत्री किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे निरंतर प्रयास

श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 10 हजार एफपीओ का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 72 लाख से अधिक किसानों को 1 हजार 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित, लगभग 47 लाख किसानों को 29 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं।

राज्य सरकार किसान हित में ले रही लगातार निर्णय

श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के लिए किसान हित पहली प्राथमिकता है। किसान सम्मान निधि में सहायता राशि को 6 हजार रुपये से अब बढ़ाकर 9 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क औषधियां और टीके उपलब्ध कराना, मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा नंबर 1962 प्रारंभ करने, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत लगभग 34 हजार पात्र गोपालकों की ऋण स्वीकृति सहित विभिन्न निर्णयों से पशुपालकों को राहत दी जा रही है। इस वर्ष के बजट में भी बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज़ की स्थापना, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट (ग्राम) का आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उपज मंडी खोलने जैसे प्रावधानों से किसान समृद्ध बनेंगे।

किसानों को बिजली, पानी उपलब्ध कराना प्राथमिकता

श्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने खेती का हर काम किया है तथा वे किसानों की समस्या को भलीभांति समझते हैं। इसीलिए राज्य सरकार किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बिजली-पानी की प्राथमिकता पर काम करते हुए राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान में 35 हजार करोड़ के एमओयू किए गए हैं। राज्य सरकार के ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णयों से किसानों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भी राज्य बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने भी विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादन संगठन मार्गदर्शिका का विमोचन किया तथा लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सफल एफपीओ पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में एफपीओ के मॉडल के रूप में बनाए गए एफपीओ ट्री नवाचार को सराहा।

भरतपुर
राज्यस्तरीय अन्त्योदय कल्याण समारोह

प्रदेश में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हो रहा सशक्त

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धान्त को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा संकल्प "गरीबी मुक्त राजस्थान" बनाना है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' शुरू की है, जिसके माध्यम से सरकार पहले चरण में 5 हजार गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी तथा इसके लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

श्री शर्मा 27 मार्च को भरतपुर में 'राजस्थान दिवस कार्यक्रम' के तहत आयोजित अन्त्योदय कल्याण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है तथा इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। अब अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति सशक्त होने के साथ ही मुख्यधारा में आ रहा है।

ब्रज की भूमि से अन्त्योदय का विचार पहुंचेगा देश-प्रदेश तक

मुख्यमंत्री ने देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजस्थान के एकीकरण में योगदान देने वाली विभूतियों को नमन करते हुए कहा कि 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान भारतीय नववर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर रेवती नक्षत्र इंद्रयोग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था। इसीलिए हमारी सरकार ने 30 मार्च के स्थान पर हर साल भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है तथा राजस्थान दिवस उत्सव की शृंखला में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्त्योदय का विचार ब्रज की भूमि से देश-प्रदेश तक पहुंचेगा।

100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित, 20 हजार पट्टों का वितरण

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने डीबीटी के माध्यम से 92 हजार से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि का हस्तांतरण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये (प्रति योजना 100 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की। कार्यक्रम में प्रदेशभर में स्वामित्व कार्ड योजना के तहत 20 हजार पट्टों का वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कलाकारों को विद्युत चालित चाक का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर एवं असिस्टिव डिवाइस वितरित की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से वर्चुअली माध्यम से जुड़े विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

8 योजनाओं के दिशा-निर्देश जारी

मुख्यमंत्री ने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना', 'गुरू गोलवलकर आशान्वित ब्लॉक विकास योजना', 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की मार्गदर्शिकाओं एवं दिव्यांगजनों के लिए 'समान अवसर नीति 2025' का विमोचन भी किया। साथ ही, 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना', मा (MAA) नेत्र वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के न्यू पैकेज व विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया।

गरीब सशक्त तो देश सशक्त

श्री शर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि गरीब, युवा, किसान व महिला के सशक्त होने से ही देश और प्रदेश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमनें सरकार में आते ही गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराकर राहत प्रदान की है तथा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से हर जरूरतमंद व्यक्ति को गुणवत्तायुक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है तथा लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर साढ़े छह हजार रुपये एवं बुजुर्ग, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह की है।

वंचितों को वरीयता हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए कार्य कर रही है। सरकार ने घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना' की घोषणा की है। साथ ही, कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, इसके लिए बजट में डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए राशि बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत समस्त राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशीलता के साथ उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। इसी दिशा में सरकार ने दिव्यांगजनों को प्रत्येक राजकीय संस्थानों में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए "दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति 2025" भी जारी की है।

सभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने आमजनों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एमएसजे कॉलेज में पूर्व सहपाठियों से संवाद किया और महारानी जया श्री जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत एवं गृह राज्यमंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भी विचार व्यक्त किए।

सुशासन का मंत्र - सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सुशासन का मंत्र है। विकास और सुशासन के इस संकल्प में जनता का साथ हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। श्री शर्मा 28 मार्च को भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित विकास एवं सुशासन उत्सव को संबोधित कर रहे थे।

आमजन को मिली सौगातें

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही 10 हजार करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने नगरीय विकास विभाग से संबंधित डेलीगेशन के आदेश, फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में डीएमएफटी के गठन, हरित अरावली विकास परियोजना, अन्नपूर्णा भण्डार और रजिस्ट्रार कार्यालय सप्ताह में 2 दिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलने के दिशा-निर्देश जारी किए। इस अवसर पर जिलों की पंचगौरव पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इससे स्थानीय क्षमताओं और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना एवं चिकित्सा ऐप का शुभारम्भ

श्री शर्मा ने कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के प्रहरी और चौथा स्तंभ हैं। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में उनकी भूमिका अहम है। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए राज्य सरकार ने पत्रकार हेल्थ कवरेज (आरजेएचएस) योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। इससे मरीज घर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।

राज्य में बढ़ी विकास की रफ्तार

श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। सरकार किसान, युवा, मजदूर, महिला के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य सरकार ने किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है, साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न नीतियां जारी की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में 12 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल, पेपर लीक प्रकरणों में गिरफ्तारी, राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू, राम जल सेतु लिंक परियोजना तथा यमुना जल समझौते जैसे जनता से किए गए प्रत्येक वादे को पूरा किया जा रहा है।

सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार अच्छा शासन वही है, जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को ध्येय मानते हुए हमारी सरकार आमजन की बेहतरी और कल्याण के लिए काम कर रही है।

युवाओं को दिया रोजगार का उपहार
7 हजार 800 से अधिक कार्मिकों को मिले नियुक्ति पत्र

कोटा
मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन

प्रदेश में रोजगार के अवसर हो रहे सृजित
- मुख्यमंत्री

"राजस्थान दिवस" नवीन राजस्थान निर्माण का संकल्प
- लोकसभा अध्यक्ष

राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रमों की कड़ी में 29 मार्च को कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि युवा शक्ति का प्रदेश के विकास और राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक योगदान सुनिश्चित किया जाए। सरकार युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के अपने संकल्प पर तेजी से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने दी युवाओं को कई सौगातें

मुख्यमंत्री ने युवा वर्ग को कई सौगातें दीं और विभिन्न विभागों में नव चयनित 7,800 से अधिक कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' की शुरुआत की और शिक्षा विभाग के दो ऐप एवं आरएसओएस अन्तर्गत ऑन डिमाण्ड परीक्षा तथा डिजिटल प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करते हुए विद्यार्थियों को बैग एवं यूनिफॉर्म की डीबीटी की शुरुआत की। कार्यक्रम में युवा नीति, स्किल नीति, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की सहायता योजना, द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन, अटल ज्ञान केन्द्र और नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र के दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

युवा नीति युवाओं के सर्वांगीण विकास का रोडमैप

श्री शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में कौशल नीति और युवा नीति का विमोचन किया गया है। राज्य सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां जारी की है, जो काम और परिणाम के प्रति हमारे समर्पण को दिखाता है।

राज्य बजट में युवा कल्याण से संबंधित ढेरों घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में युवा कल्याण के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिनमें वन विभाग में 1750 कर्मचारी, 4 हजार पटवारी और 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती सहित कुल सवा लाख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 67 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 96 हजार से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही, ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी जैसी अटकी हुई भर्तियों को भी शुरू किया गया है, जिनमें 53 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शिक्षा और कौशल विकास में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की और राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 को युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

राजस्थान दिवस

भव्य संस्कृति साकार

अल्बर्ट हॉल पर राज्यस्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े एवं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान दिवस महोत्सव के अंतर्गत 30 मार्च को अल्बर्ट हॉल पर आयोजित राज्यस्तरीय सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी कलाकारों ने अल्बर्ट हॉल के मंच पर प्रदेश की गौरवशाली कला की झलक प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में भव्य आतिशबाजी भी की गई।

जयपुर
निवेश उत्सव

2030 तक राज्य बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की आज ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गई है।

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केन्द्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज्म और डेडिकेटेड टीम बनाई है, जो इनकी सक्रिय निगरानी कर रही है।

16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी एमओयू पर भी लागू होगी डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी की घोषणा की, जो 15 मार्च तक राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू निष्पादित करने वाले धारकों को शामिल करती है। इसके साथ ही, 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले नए एमओयू पर भी यह नीति लागू होगी, और एमओयू धारक 15 मई से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका लाभ उठा सकेंगे।

18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की होगी स्थापना, राजस्थान फाउण्डेशन के 14 नए चैप्टर्स होंगे शुरू

श्री शर्मा ने बताया कि सरकार विभिन्न सेक्टर्स की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किए गए 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है, ताकि प्रदेश मैन्यूफैक्चरिंग का पॉवरहाउस बन सके। इसके साथ ही, सौर और पवन ऊर्जा की प्रचुरता ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के तहत 14 नए चैप्टर्स गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला और दोहा में खोलने की घोषणा की। इसके अलावा, विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा।

राजस्थान लॉजिस्टिक नीति-2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 के साथ ही विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे निवेशक अपने प्रस्तावों की प्रगति ट्रैक कर सकेंगे और अधिकारियों से आसानी से जुड़ सकेंगे।

रन फॉर फिट राजस्थान

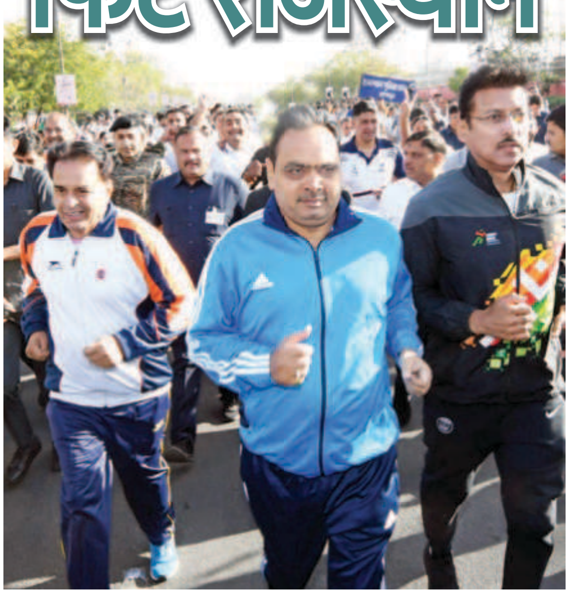

राजस्थान दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शृंखला में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 29 मार्च को अमर जवान ज्योति पर आयोजित 'रन फॉर फिट राजस्थान' दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने तथा उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था। 'रन फॉर फिट राजस्थान' इसी संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ भूखंड आवंटन, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से खिलाड़ियों को सुरक्षा कवच भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन ओलंपिक-2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और जयपुर में 20 करोड़ की लागत से "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स" की स्थापना की जाएगी।

अत्याधुनिक पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

राजस्थान दिवस कार्यक्रम की शृंखला में, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम 'सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह' से 150 नए अत्याधुनिक पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

फाल्गुनी बयार में सौगातों की बौछार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत-2047 की परिकल्पना को मूर्तरूप देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी विजन के साथ 19 फरवरी को विधान सभा में राज्य बजट 2025-26 पेश किया गया। होली से ठीक एक दिन पहले 12 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के बजट 2025-26 में की गई जन कल्याण की ढेरों योजनाओं के रूप में खुशियों और विकास के रंगों की गुलाल से राजस्थानवासियों के विश्वास को मजबूती प्रदान की।

इसी के साथ राज्य विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने 27 फरवरी को राज्य विधान सभा में आय-व्ययक अनुमान 2025-26 पर सामान्य चर्चा के बाद जवाब प्रस्तुत करते हुए कई नवीन घोषणाएं प्रस्तावित कीं। प्रस्तुत हैं विकास के विभिन्न आयामों को सुनिश्चित करतीं नई घोषणाओं के रूप में विकास और विश्वास के अलग-अलग रंग।

पेयजल

- पेयजल सम्बन्धी समस्या के तत्काल निराकरण के लिए प्रत्येक जिला कलक्टर को एक करोड़ रुपये का अनटाईड फंड।
- आगामी गर्मी को देखते हुए बजट में पूर्व में घोषित एक हजार 500 हैण्डपम्प की संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में दो हजार 500 हैण्डपम्प लगाये जाने की घोषणा।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 330 करोड़ (तीन सौ तीस करोड़) रुपये से अधिक के कार्य चरणबद्ध रूप से करवाये जाने की घोषणा।

औद्योगिक विकास

- शाहपुरा-भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क व लालसोट-दौसा में Wood Park की स्थापना की जायेगी।
- पर्यावरणीय नियमों की पालना करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ऑटो नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- उद्यमियों को GST, VAT एवं विद्युत शुल्क सम्बन्धी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन, **इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम** (ITMS) के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेंगे।

राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान...

ऊर्जा

राज्य में विद्युत प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 33 केवी, 132 केवी और 220 केवी क्षमता के विभिन्न क्षेत्रों में जीएसएस।

सड़क व यातायात

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए घोषित 10-10 करोड़ रुपये की राशि में से 5 करोड़ रुपये लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाये जाने की घोषणा।
- बजट में घोषित तीन प्रमुख हाईवे पर जीरो एक्सीडेन्ट जोन के क्रम में अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों चालकों हेतु 'सुविधा एवं विश्राम स्थलों' की स्थापना की घोषणा।
- सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 हजार नवीन परमिट जारी किये जाने की घोषणा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्यों की घोषणा।
- प्रदेश में सड़कों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु एक हजार 870 करोड़ (एक हजार आठ सौ सत्तर करोड़) रुपये से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाये जाने की घोषणा

सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधायें

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किये जाने की घोषणा। विकास प्राधिकरण एवं इनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय व 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति।
- नगर विकास न्यास एवं उन शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम एवं नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति।
- अन्य समस्त क्षेत्रों में 5 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय एवं 2 हजार 500 वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी की जा सकेगा।
- पुनर्गठन एवं उप विभाजन के प्रकरणों में पट्टा जारी करने की सक्षमता तक पुनर्गठन एवं उप विभाजन भी स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी।
- विकास प्राधिकरणों तथा नगर विकास न्यासों के क्षेत्राधिकार में स्थित आवासीय भूखण्डों का नीलामी के माध्यम से आवंटन में लगने वाले अत्यधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को, आगामी वर्ष ऐसे भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने की घोषणा।
- भिवाड़ी विकास प्राधिकरण, दौसा-बांदीकुई नगर विकास न्यास व बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन किये जाने की घोषणा।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृहकर प्रणाली का व्यापक सरलीकरण किया जायेगा।
- प्रदेश के विभिन्न शहरों में 50 हजार के स्थान पर 1 लाख स्ट्रीट लाईट लगाए जाने की घोषणा।
- उप पंजीयक कार्यालयों का समय सप्ताह में दो दिन-सोमवार एवं शुक्रवार को, बढ़ाकर प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक किये जाने की घोषणा।
- सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा।
- गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे व दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिख, रियाद,

टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कम्पाला एवं दोहा में राजस्थान फाउण्डेशन के नये चेप्टर्स।

- नवगठित जिलों में डीएमएफटी की स्थापना।
- 25 नवीन नगर पालिकाओं के गठन, 4 नगरीय निकायों के क्रमोन्नयन की घोषणा।
- विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाईयों एवं न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन की घोषणा।
- एमएलए लेड योजना में किसी भी गैर राजकीय संस्था को 10 लाख रूपये तक की सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रूपये करने की घोषणा।
- राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का होगा गठन।
- प्रदेश के नवगठित 8 जिलों में 'मिनी सचिवालय' बनाये जाने की घोषणा।
- लालकोठी-जयपुर स्थित कार्मिक विभाग की भूमि पर राज्यस्तरीय कार्यालय हेतु 'ऑफिस कॉम्पलैक्स' की स्थापना की घोषणा।

प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान तत्काल सहायता, बचाव कार्य के साथ-साथ आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए

I. जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग एवं State Disaster Reserve Force (SDRF) के लिए 55 (पचपन) Quick Response Vehicles (QRV) उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर लगभग 120 करोड़ (एक सौ बीस करोड़) रुपये का व्यय होगा।

II. प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित District Emergency Operation Centres के सुदृढ़ीकरण हेतु 41 करोड़ (इकतालीस करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे।

- प्रदेश के बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर एवं बांसवाड़ा में अग्निशमन Aerol Hydraulic Ladder Platform उपलब्ध करवाने के साथ ही, शेष रही निकायों एवं नवीन निकायों में 3 से 4 हजार 500 लीटर क्षमता के Fire Water Tenders उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टेण्ड सहित अन्य विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित।
- जोजरी नदी-जोधपुर के जीर्णोद्धार व प्रदूषण सुधार कार्य के अन्तर्गत नादंडी एवं झालामंडल क्षेत्र में STPs का निर्माण एवं सीवर मुख्य ट्रंक लाइनों के पुनर्वास का कार्य तथा गंदे पानी हेतु Sewerage Pumping Station के कार्य 176 करोड़ (एक सौ छिहत्तर करोड़) रुपये की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित।

"देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि हमारी सरकार सिटीजन फर्स्ट के विजन के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रमुख फैसलें लेते वक्त गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) सदैव हमारी प्राथमिकता में रहते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूलमंत्र को प्रतिबिंबित करता है।"

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

- भविष्य में 'राजस्थान दिवस' चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जायेगा।
- युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति से परिचय करवाने हेतु 'भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम' प्रारम्भ करने की घोषणा।
- जनजाति कलाकार वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केन्द्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थल, चित्रकारी, भिति चित्र, काष्ठ व प्रस्थर कला, नृत्य एवं गायन के प्रलेखन कार्य हेतु 'सौंध माटी आदिधरोहर प्रलेखन योजना'

प्रारम्भ किये जाने की घोषणा।

- प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के सदृश्य स्थानों की दीवारों पर स्थानीय चित्रकारों द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति का चित्रण करती हुई Paintings चरणबद्ध रूप से करवायी जानी प्रस्तावित। इस हेतु आगामी वर्ष 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का व्यय किया जायेगा।
- प्रदेश में पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

युवा विकास एवं कल्याण

- युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष में वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, 4 हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूल शिक्षकों की भर्ती किये जाने की घोषणा।
- प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एकबारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ करने की घोषणा।
- आगामी वर्ष सम्भाग स्तरीय सेन्टर फॉर एडवान्स्ड स्किलिंग एंड कैरियर काउसंलिंग स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100-100 करोड़ रुपये के कार्य।
- प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेन्टिसशिप प्रोग्राम जॉइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपंड का विकल्प दिये जाने की घोषणा।
- जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में आईआईटी-जोधपुर का कैम्पस स्थापित किये जाने की घोषणा।
- प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र से 'मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान' प्रारम्भ किये जाने की घोषणा।

- वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक-बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अन्तर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ किए जाने की घोषणा।
- आदर्श वेद आवासीय विद्यालय, रैवासा-सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ, गोमरख धाम-बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा। साथ ही, राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जायेगा।
- प्रदेश के युवाओं को खेल सम्बन्धी समस्त आवश्यक सुविधायें प्रदान किये जाने की दिशा में खेल निदेशालय की स्थापना किये जाने की घोषणा।
- भीलवाड़ा में मल्टीपरपज स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, श्रीगंगानगर में साईकिल ट्रेक तथा कुम्हेर-डीग व केशोरायपाटन-बूंदी में खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा।
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अन्तर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशन्स व राज्य सरकार के अधीन सेन्टर फॉर इकोनोमिक ट्रान्सफॉर्मेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की स्थापना की घोषणा।
- नवीन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी लाई जाएगी।
- राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ करने की घोषणा।
- कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक निदेशालय की स्थापना की घोषणा।
- 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने की घोषणा।
- युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर 'Viksit Bharat Young Leaders Dialogue' आयोजित किये जाने के साथ ही, आगामी वर्ष Youth Festival का आयोजन करवाये जाने की घोषणा।
- युवाओं को Startup तथा Digital Ecosystem से अधिक से अधिक संख्या में जोड़कर उन्हें उन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु आगामी वर्ष TiE Global से जुड़ते हुए Rajasthan Digi Fest का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 15 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

- छत्तीसगढ़ में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रदेश से भाग लेने वाले लगभग 2 हजार 500 प्रतिभागियों की तैयारी हेतु जिला/Block स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों तथा शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना व क्रमोन्नयन, नवीन संकाय/विषय खोले जाने व निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।
- जैतारण-ब्यावर में हॉकी खेल अकादमी की स्थापना, अजमेर में multipurpose स्टेडियम का निर्माण, माचड़ा (विद्याधरनगर)-जयपुर में Play Ground व माउंट आबू-सिरोही में पोलो ग्राउण्ड के उन्नयन कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, औंसिया-जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन-पाली, प्रतापनगर-जयपुर एवं डीडवाना में खेल स्टेडियम के निर्माण करवाये जायेंगे।
- सभी नवगठित 8 जिलों में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त डेडीकेटेड थैलेसीमिया सेन्टर्स की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अधीन किए जाने की घोषणा।
- प्रदेश में अति गम्भीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किये जाने की घोषणा । इसके अतिरिक्त, 8 मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में सम्पूर्ण स्तनपान प्रबन्धन केन्द्र एवं 11 अन्य चिकित्सालयों में स्तनपान प्रबन्धन इकाई की स्थापना की घोषणा।
- आमजन को पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 30 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की घोषणा।
- RGHS के तहत कैंसर पीड़ितों को सुलभता से इलाज उपलब्ध कराने हेतु Onco Facilitation Programme शुरू किया जायेगा।

"2024-25 में जीएसडीपी 197 बिलियन डॉलर रहेगी तथा वर्ष 2025-26 में बढ़कर 230 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकड़ा 350 बिलियन डॉलर हो जाएगा। जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आंकलन करें तो हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी।"

- MAA योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उच्च तकनीक से किये जाने वाले नये procedures शामिल किये जाने प्रस्तावित हैं। ये procedures हैं- Robotic Surgery, Neuro Surgery Procedures, Plastic Surgery and Skin Transplant, Cardiothoracic and Vascular Surgery.
- प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट नर्सिंग सेवायें प्रदान करने के लिए Oncology, Midwifery, Forensic सहित 14 नवीन Advanced Courses शुरू किये जाने की घोषणा। साथ ही, संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 16 प्रकार के नवीन Para Medical Courses भी शुरू किये जायेंगे।
- 25 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की घोषणा।
- मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय व सैटेलाइट चिकित्सालयों में बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए Hospital Manager का Cadre बनाया जाना प्रस्तावित है।

- मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय व सैटेलाइट चिकित्सालयों में hospital support services– laundry, canteen, house keeping, security, parking, garden आदि का सुदृढ़ीकरण Out Sourced / PPP Mode पर किया जायेगा।
- प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, upgradation, भवन निर्माण, repair व maintenance सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।
- Rajasthan Digital Health Mission के अगले चरण में मरीज के One Time Registration हेतु IPD मरीजों के लिए Single Window Registration System लागू किये जाने की घोषणा। साथ ही, hassle free service delivery हेतु MAA योजना तथा RGHS Portal को IHMS (Integrated Health Management System) के अन्तर्गत integrate भी किया जायेगा।

सामाजिक सुरक्षा

- "गरीबी मुक्त राजस्थान" की परिकल्पना को साकार करने हेतु 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना' प्रारम्भ किये जाने की घोषणा। प्रथम चरण में 5 हजार गाँवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- युवा दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने के लिए 2 हजार 500 दिव्यांगजन को स्कूटी दिये जाने की घोषणा।
- उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का होगा सम्मान। प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टेबलेट उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा।
- एमबीसी कल्याण हेतु देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान।
- विशेष आवश्यकता वाले (Specially abled) विद्यार्थियों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से Building को accessible बनाये जाने व Portable Ramps, Disable Friendly Toilets एवं Signages का निर्माण करवाया जायेगा। इन पर लगभग 60 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- आगामी वर्ष 5 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की 50 करोड़ रुपये व्यय कर मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है।

कृषि एवं पशुपालन

- ग्रामीण क्षेत्र में अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करते हुए 30 दिवस किये जाने की घोषणा।
- माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50 हजार के स्थान पर अब 60 हजार सौर ऊर्जा पम्पों हेतु अनुदान उपलब्ध करवाने की घोषणा।
- किसानों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु वन टाईम सेटलमेंट योजना की घोषणा।
- भरतपुर की अनाज व सरसों मण्डी शहर से बाहर स्थानान्तरित होंगी। साथ ही, बहरावण्डा कलां सवाई माधोपुर, नासिरदा-टोंक व सेखाला-जोधपुर में गौण कृषि मण्डियाँ स्थापित की जायेंगी।
- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की घोषणा।
- देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलैंस इन्डीजीनस फार्म होगा स्थापित।
- प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बगड़-झुंझुनूं व गंगापुर-भीलवाड़ा को पॉलीक्लिनिक में तथा पशु चिकित्सालय बावड़ीखुर्द-फलौदी को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु उप चिकित्सा केन्द्र, धीरपुरा-जोधपुर को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की संकल्पना कैच द रैन से प्रेरणा लेकर कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अन्तर्गत सीएसआर के माध्यम से 5 हजार जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाए जाने की घोषणा।
- जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 में पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित 300 हेक्टेयर तक के 3 हजार 236 (तीन हजार दो सौ छत्तीस) छोटे बांधों को पुनः जल संरचनाओं के समुचित प्रबंधन हेतु जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य 240 करोड़ (दो सौ चालीस करोड़) रुपये से अधिक की लागत से करवाये जाने की घोषणा।

- पशु रोग नियंत्रण हेतु पशुपालकों को गुणवत्तायुक्त टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए cold chain युक्त वाहन एवं Ice Linear Refrigerators उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- कोटा में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बाड़ी-धौलपुर को Polyclinic में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- प्रदेश में रियाबड़ी (मेड़ता)-नागौर में कृषि उपज मण्डी, माखूपुरा-अजमेर, बर (जैतारण)-ब्यावर में फल सब्जी मण्डी की स्थापना की जायेगी। साथ ही, कृषि फल मण्डी अजमेर में जीर्णोद्धार व प्लेटफार्म सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

हरित विकास

- मोखला परेवर-जैसलमेर व बुचारा मेन-जयपुर में नवीन कन्जर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़ में संवर्धन कार्य।
- प्रदेश के टाईगर रिजर्वस् में आवासरत ग्रामीणों को अन्यत्र पुनर्वासित करने के लिए देय पैकेज को रिवाइज किए जाने की घोषणा।
- टाडगढ़-रावली, फुलवारी की नाल एवं माउण्ट आबू वन्य जीव अभयारण्यों के इको सेंसिटिव जोन हेतु मास्टर प्लान तैयार किए जाने की घोषणा।
- प्रदूषण मण्डल में कन्सेंट आवेदनों के बेहतर प्रबंधन हेतु ऑनलाईन प्रणाली का उन्नयन किया जायेगा।
- अधिक घनत्व एवं जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में Rare, Threatened, Endangered Species के संरक्षण व संवर्धन हेतु आगामी 2 वर्षों में 40 Plant Micro Reserves 16 करोड़ (सोलह करोड़) रुपये की लागत से बनाये जायेंगे।
- गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर वनाधिकार प्रकोष्ठ (Forest Rights Cell) का 18 (अठारह) जिलों में गठन किया जायेगा।
- राज्य में समन्वित कीट प्रबंधन के लिए 10 प्रयोगशालाएं Tricoderma एवं NPV जैसे Bio-Agents तैयार कर रही है। आगामी वर्ष Bio-Agents की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए 100 मीट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न Agro-Climatic Zones के अनुरूप उचित Species एवं उनमें सुधार (Agri-Biologicals) से सम्बन्धित Bio-informatics Data Base स्थापित किया जाना प्रस्तावित।
- Plastic की Recycling एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु Plastic Waste Collection Campaign के तहत मोबाइल वैन तथा Plastic Waste Exchange Booths के माध्यम से Plastic Waste Collection करने तथा Plastic Waste के बदले में कपड़े के थैले वितरित किये जायेंगे।

"हमारे कार्य करने की गति के कारण लगातार न सिर्फ घोषित कार्य स्वीकृत हो रहे हैं अपितु धरातल पर भी आ रहे हैं। गत बजट की घोषणाओं की प्रगति जहाँ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिये गये जवाब 7 फरवरी, 2025 के दिन 62 प्रतिशत थी, बजट प्रस्तुति 19 फरवरी, 2025 के दिन बढ़कर 73 प्रतिशत हो गई। यह प्रगति अब 82 प्रतिशत हो चुकी है। वर्तमान बजट की भी 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। अभी तो वर्ष 2025-26 प्रारम्भ भी नहीं हुआ और हमने घोषणाओं के क्रियान्वयन पर कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है।"

सुशासन

- प्रदेश में आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाये जाने का विनिश्चय के क्रम में आगामी वर्ष में 25 हजार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाने की घोषणा। इसके साथ ही, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष में 250 और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के गठन की घोषणा।
- प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा। साथ ही, पुलिस हेतु 400 अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा।
- नवीन न्याय संहिताओं के समुचित क्रियान्वयन की दृष्टि से फोरेन्सिक साक्ष्य संकलन हेतु 70 मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स उपलब्ध करवाए जाने, अभियोजन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 250 नवीन पद सृजित किये जाने एवं विभिन्न उपकरणों हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किए जाने की घोषणा।
- State Data Centre (SDC) के अन्तर्गत AI/ML आधारित Research, Simulation, VFX, Gaming, Advance Analytics एवं Image Processing के लिए High Performance Computing (HPC) server infrastructure की स्थापना 65 करोड़ (पैंसठ करोड़) रुपये की लागत से किये जाने की घोषणा। साथ ही, State Data Centre (SDC) के संचालन को automate किया जाना एवं Cyber Security को बढ़ाते हुए Comprehensive Red Teaming Strategy लागू किया जाना भी प्रस्तावित है।
- ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को जोड़ते हुए, राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के सृजन, सीमांकन व क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के सम्बन्ध में समुचित परीक्षण तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा।
- प्रदेश में संसाधनों के समुचित उपयोग एवं आधारभूत संरचना पर व्यय में बचत के उद्देश्य से remote sensing एवं GIS प्लेटफॉर्म को Artificial Intelligence से जोड़ते हुए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान कर 'राजधरा 2.0' स्थापित किये जाने की घोषणा। साथ ही, RajKaj, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग के IT Platforms एवं IT तंत्र का उन्नयन किया जाना भी प्रस्तावित है।
- सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों की efficiency में वृद्धि हेतु motivate करने के लिए उनसे सम्बन्धित सभी आवश्यक राजकीय प्रक्रियायें यथा-पदस्थापन, पदोन्नति एवं सेवा नियमों से सम्बन्धित कार्य Hassle free, online पद्धति से हो सके, इस दृष्टि से 15 करोड़ (पन्द्रह करोड़) रुपये की लागत से Integrated Human Resource Management System (IHRMS) बनाया जाना प्रस्तावित है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक, पुलिस इकाइयों एवं न्यायालयों की स्थापना व क्रमोन्नयन किया जायेगा।
- प्रदेश के विकास में आमजन की महती भूमिका एवं योगदान को देखते हुए, नवाचार कर समाज से जुड़ी समस्या का उत्कृष्ट व उल्लेखनीय समाधान करने का कार्य करने वाले आमजन को प्रोत्साहित करने के लिए आगामी वर्ष से Atal Innovation Awards दिये जाने की घोषणा।
- कार्यप्रभारित कार्मिकों की वेतन विसंगति का निराकरण करने हेतु पूर्व में प्राप्त वेतनमान/पे-लेवल को संरक्षित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

आभार

मुख्यमंत्री निवास पर आभार सभा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को बजट सौगातों के लिए धन्यवाद देने जयपुर जिले से आए लोगों की आभार सभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं के हितों के लिए हमारी सरकार लगातार निर्णय ले रही है। कार्यक्रम के दौरान 'एक ही लाल, भजनलाल भजनलाल' और 'दमदार मुख्यमंत्री, दमदार फैसले' जैसे नारों से पूरा पाण्डाल गुंजायमान हो उठा तथा लोगों ने अपूर्व बजटीय घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत किया।

भरतपुर एवं डीग जिले को दी गई सौगातों के लिए जताया आभार

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे के दौरान जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 में भरतपुर एवं डीग जिले को दी गई सौगातों के लिए उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की और संबंधित अधिकारियों को आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की घोषणा के लिए सिख समुदाय के प्रतिनिधिमण्डल ने जताया आभार

सिख समुदाय के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा गुरू गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के नाम पर जयपुर में छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिनन्दन करते हुए उन्हें गुरू गोबिंद सिंह एवं साहिबजादों की तस्वीर एवं शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट की।

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान

लोकतंत्र, संवाद और विचारशीलता का अनूठा केंद्र

- **डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा**, उप निदेशक

राजस्थान विधान सभा के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की विश्वस्तरीय सुविधाओं का शुभारम्भ आठ मार्च को लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी द्वारा सनातन परंपरा और वैदिक रीति से हवन में आहूति अर्पित कर किया गया।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त

प्रदेश में नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब की तर्ज पर जयपुर में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। क्लब में बेसमेंट, भूतल और पांच तलों का 1 लाख 95 हजार फीट निर्माण है। जयपुर में विधान सभा के समीप 4 हजार 948 वर्गमीटर भूखण्ड पर 80 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यहां रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेन्स हॉल, वीआईपी लाउंज, जिम, सैलून, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस एवं लॉन टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए कमरों का भी निर्माण किया गया है। यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि देश के विधानमण्डलों में राजस्थान विधान सभा ऐसी पहली विधान सभा है, जहां कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है।

विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केन्द्र

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान मानवीय विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा। पूर्व मुख्यमंत्रीगण, पूर्व विधान सभा अध्यक्षगण भी इस क्लब के सदस्य हैं। प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के अनुभवों से नये विधायकगण लाभान्वित होंगे। क्लब में विभिन्न अवसरों पर कार्यशालायें और सेमिनार आयोजित होंगी। विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं को इसका सर्वाधिक लाभ मिल सकेगा। यह क्लब न केवल विधायकों के लिए, बल्कि राजस्थान विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खोला गया है। यहा आजीवन सदस्यता, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता और सामान्य सदस्यता इस क्लब को समावेशी रूप देते हैं। यह क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा।

संसदीय परंपराएं होंगी सुदृढ़

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान संसदीय परंपराओं को सुदृढ़ करने का माध्यम बनेगा। क्लब में सदस्यों के मध्य संसदीय परंपराओं पर चर्चा और परिचर्चाएं होंगी। नये विधायकगणों को परंपराओं को जानने का मौका मिलेगा।

संवाद, सहमति और सुशासन का केंद्र

यह क्लब केवल एक भवन ही नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक विमर्श, विचारशीलता और नीति-निर्माण को दिशा देने वाला मंच है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि सतत संवाद और सहमति से आगे बढ़ता है। यह क्लब नीति-निर्माण और सुशासन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दिल्ली में संविधान क्लब की परिकल्पना 1947 में संविधान निर्माण के दौरान हुई थी। उस समय अनौपचारिक चर्चा और नीतिगत संवाद के लिए एक मंच की आवश्यकता महसूस हुई थी। राजस्थान में स्थापित यह क्लब भी लोकतांत्रिक संवाद और विचार-विमर्श का प्रमुख केंद्र बनेगा। यह विधायकों को विचारशीलता, नीति-निर्माण और सुशासन पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देगा।

लोकतंत्र को मजबूती का विशेष प्रयास

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों संविधान, समानता और जनप्रतिनिधित्व को मजबूती देने का विशेष प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति को क्लब में संविधान की गरिमा और विधायी प्रक्रिया के महत्व का एहसास होगा। यह क्लब केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक विचार है, जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएगा। साथ ही, पुस्तकालय, सभागार और विश्राम क्षेत्र कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक होंगे।

शुभारंभ सनातन परंपरा और वैदिक रीति से

लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला, मुख्यमंत्री श्री शर्मा और विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने भारतीय सनातन परम्परा और वैदिक रीति के साथ हवन में पूर्ण आहूति, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण, क्लब की सुविधाओं का फीता खोलकर और दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ क्लब का शुभारम्भ किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, राज्य संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल सहित मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, विधायकगण और पूर्व विधायकगण भी मौजूद थे।

"राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जहां विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। यह क्लब अन्य प्रदेशों के जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा देगा। क्लब जनप्रतिनिधियों के लिए विचारों के आदान प्रदान, परस्पर सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्लब संविधान के तीनों अंगों से जुडे पदाधिकारियों के मध्य संवाद को नये आयाम देगा। दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के संचालन की तर्ज पर इस क्लब में सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह क्लब विधान सभा और विधायक आवास के नजदीक होने के कारण अधिक उपयोगी बन गया है।"

-श्री वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष

जैव विविधता का नुकसान वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा

जैव विविधता संरक्षण में सालाना 143 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया जाता है, लेकिन यह हर साल अनुमानित 824 बिलियन अमरीकी डॉलर की ज़रूरत से यह काफी कम है।

20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में, 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस (WWD) घोषित किया गया है। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय: प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora–CITES) पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस अब वन्यजीवों को समर्पित वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।

हम मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वन्यजीवों और जैव विविधता-आधारित संसाधनों पर निर्भर हैं। भोजन से लेकर ईंधन, दवाइयों, आवास और कपड़ों तक, प्रकृति द्वारा हमें और हमारे ग्रह को मिलने वाले लाभों और सुंदरता का आनंद लेने के लिए, लोग यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र सतत् हों और पौधे और पशु प्रजातियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए अस्तित्व में रह सकें।

इस दिन महासभा ने दुनिया को वन्यजीवों के पारिस्थितिक, आनुवांशिक, वैज्ञानिक व सौंदर्य सहित विभिन्न प्रकार से अध्ययन-अध्यापन को बढ़ावा देने को प्रेरित किया है। विभिन्न जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों के अस्तित्व की रक्षा भी इसका उद्देश्य है। यूएन के अनुसार एक मिलियन से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने का अनुमान है और तीव्र होते ट्रिपल प्लैनेटरी संकट का सामना कर रहे वन्यजीवों के संरक्षण के लिए धन उपलब्धता के नए स्रोत पहले से कहीं अधिक जरूरी है। इसी कारण वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम **“Wildlife Conservation Finance: Investing in People and Planet”** है।

संवाद में संवेदना जरूरी है, शब्द नहीं

वन्य प्राणियों से मिलकर अभिभूत हुए प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के दूसरे दिन 4 मार्च को गुजरात के जामनगर में वन्य प्राणियों की बचाव व पुनर्वास पहल 'वनतारा केन्द्र' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वनतारा में कई तरह के रेस्क्यू किए गए वन्य प्राणियों का हालचाल जाना और उनसे संवाद किया। इस यात्रा ने प्रधानमंत्री की वन्यजीवों, उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के प्रयासों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री ने संचालकों से केंद्र की व्यापक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन और आईसीयू सेवाओं से सुसज्जित अत्याधुनिक वन्यजीव अस्पताल शामिल है। इसका उद्देश्य बचाए गए जानवरों को उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। अपने दौरे के दौरान, पीएम मोदी कई तरह के जानवरों के साथ संवाद करते देखे गए, जिनमें एशियाई शेर के बच्चे, एक सफेद शेर का बच्चा, एक क्लाउडेड तेंदुआ का बच्चा और कैराकल के बच्चे शामिल थे। श्री मोदी ने जिस सफेद शेर के बच्चे को खाना खिलाया, उसका जन्म उसकी मां को बचाए जाने के बाद केंद्र में हुआ था, जबकि कैराकल, जो कभी भारत में आम थे, लेकिन अब एक दुर्लभ प्रजाति हैं, को भविष्य में जंगल में छोड़ने के लिए वनतारा में एक कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम के तहत पाला जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने एमआरआई कक्ष का भी दौरा किया, जहां उन्होंने एक एशियाई शेर का एमआरआई स्कैन होते देखा। ऑपरेशन थियेटर में, उन्होंने एक तेंदुए की जीवन रक्षक सर्जरी देखी, जिसे एक वाहन ने टक्कर मार दी थी और इलाज के लिए केंद्र में लाया गया था। यात्रा के सबसे खास पलों में से एक पीएम मोदी की एक गोल्डन टाइगर और चार स्नो टाइगर्स से मुलाकात थी, जिन्हें एक सर्कस से बचाया गया था, जहां उन्हें करतब दिखाने के लिए मजबूर किया गया था। वे एक सफ़ेद शेर और एक हिम तेंदुए के साथ भी आमने-सामने बैठे। उनका संवाद कई तरह के जानवरों से हुआ, जिनमें चिम्पांजी, ओकापी, ओरंगउटान, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ और ज़ेबरा शामिल थे।

उन्होंने एक जिराफ़ और एक सींग वाले एक अनाथ गैंडे के बछड़े को भी खिलाया। पीएम मोदी ने कुछ दुर्लभ प्रजातियों को भी देखा, जिसमें दो सिर वाला सांप, दो सिर वाला कछुआ, एक टपीर, कृषि क्षेत्रों से बचाए गए तेंदुए के बच्चे, विशालकाय ऊदबिलाव, बोंगो (एक प्रकार का मृग), सील और हाथी शामिल थे, जो एक विशेष जकूज़ी थेरेपी का आनंद ले रहे थे। इस यात्रा का सबसे प्रतीकात्मक क्षण तब आया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बचाए गए तोतों को उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ा। यह केंद्र के बचाए गए वन्यजीवों के पुनर्वास और स्वतंत्रता के मिशन का रूपक था। वनतारा में अपने पूरे दौरे के दौरान, उन्होंने पशु चिकित्सकों, देखभाल करने वालों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और इस विशाल सुविधा के प्रबंधन और संचालन के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उद्घाटन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी के साथ श्रीमती नीता अंबानी, श्री अनंत अंबानी और श्रीमती राधिका मर्चेंट भी शामिल हुए।

मौन संवाद

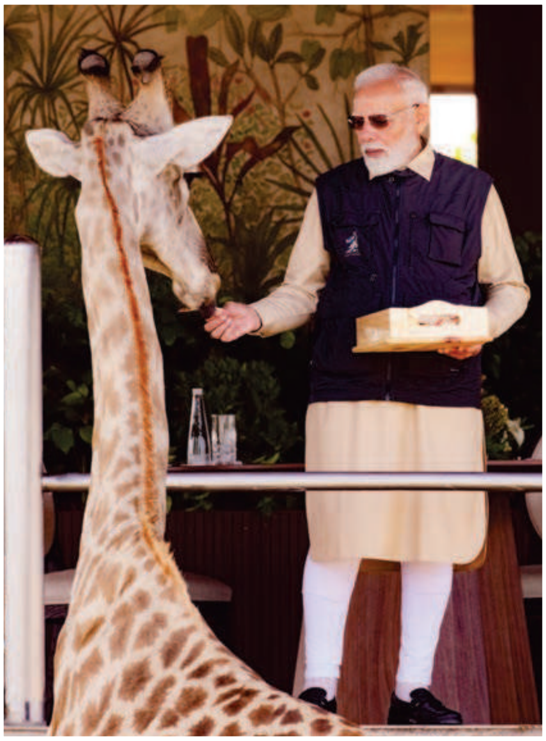

अनूठी संरक्षण और पुनर्वास पहल

"वनतारा का उद्घाटन किया, जो एक अनूठी वन्यजीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास पहल है, जो पारिस्थितिकी स्थिरता और वन्यजीव कल्याण को बढ़ावा देते हुए जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। मैं अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम की इस बेहद दयालु प्रयास के लिए सराहना करता हूं।"

"वनतारा जैसा प्रयास वास्तव में सराहनीय है, यह हमारे सदियों पुराने लोकाचार का जीवंत उदाहरण है कि हम अपने उन जीव-जन्तुओं की भी रक्षा करते हैं, जो इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहते हैं। जामनगर में वनतारा की मेरी यात्रा की कुछ झलकियां...

लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व

राज्य सरकार की पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण की प्रतिबद्धता

जयेश पण्डया, सहायक जनसंपर्क अधिकारी

झीलों की नगरी उदयपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां की अरावली पहाड़ियां कई वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास हैं, जिनमें तेंदुआ (लेपर्ड) एक प्रमुख शिकारी प्रजाति है। अमरख महादेव क्षेत्र भी इसी जैव विविधता का हिस्सा है और हाल के वर्षों में यहां तेंदुओं की बढ़ती उपस्थिति दर्ज की गई है। तेंदुओं के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व (तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र) विकसित करने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2025-26 में वन्यजीव संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई।

लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व की आवश्यकता

उदयपुर और उसके आसपास शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तेंदुओं के प्राकृतिक आवास सीमित हो रहे हैं। जंगलों के कटाव और शिकार की संभावनाओं में कमी के कारण तेंदुए मानव बस्तियों के करीब आने लगे हैं। इससे पालतू जानवरों और मनुष्यों पर हमले बढ़े हैं, जिससे स्थानीय आमजन में भय का माहौल बना है। तेंदुआ भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। अमरख महादेव क्षेत्र में एक संरक्षित रिजर्व विकसित होने से तेंदुओं को एक सुरक्षित आवास मिलेगा, जहां वे बिना किसी मानव हस्तक्षेप के अपने प्राकृतिक परिवेश में रह सकेंगे।

तेंदुआ एक शीर्ष शिकारी (Apex Predator) है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संरक्षण से क्षेत्र की अन्य वन्यजीव प्रजातियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यह पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में नियंत्रण स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण घटक है।

अमरख महादेव लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व विकसित होने से उदयपुर के निकट ही इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पर्यटकों को वन्यजीव सफारी, नेचर वॉक और फोटोग्राफी जैसी गतिविधियों का अनुभव मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी होगी, वहीं एक संरक्षित क्षेत्र होने के कारण यह रिजर्व वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को तेंदुओं के व्यवहार, उनकी आबादी और संरक्षण की चुनौतियों पर अध्ययन करने का अवसर देगा। साथ ही, छात्रों और आम जनता को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) अजय चित्तौड़ा के अनुसार वर्तमान में इस क्षेत्र में करीब 12 तेंदुए निवास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में तेंदुए के अलावा हिरण, सियार, भालू, जंगली सूअर और अन्य प्रजातियों के विविध वन्य जीव पाए जाते हैं। विभाग ने रिजर्व के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। करीब 30.79 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को अगले दो साल में पूरा किया जाना है। रिजर्व के भीतर वन्यजीवों की सुरक्षा और क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए 68 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 6 फीट होगी।

फ़ोटो साभार : लक्ष्मण पारंगी

30.79 करोड़ की लागत से 2 वर्षों में आकार लेगा लेपर्ड कंज़र्वेशन रिजर्व

वाटरहोल्स में पानी की आपूर्ति के लिए 48 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही शाकाहारी वन्यजीवों के लिए 100 हेक्टेयर का घास का मैदान बनाया जाएगा। चीतल, हिरण, सांभर और चिंकारा जैसी शाकाहारी वन्यजीव प्रजातियों के लिए 3.5 हेक्टेयर में बाड़े बनाए जाएंगे।

रिजर्व की सीमा अमरख जी महादेव मंदिर से कुराबड़ होते हुए देबारी तक फैलेगी। उदयसागर झील के अलावा, इसमें मावली और कुराबड़ क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल होंगे। रिजर्व के भीतर तीन पेट्रोलिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई 33 किमी, 20.5 किमी और 53.5 किमी होगी। रिजर्व के भीतर छह स्टाफ गार्ड पोस्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पानी की आपूर्ति और निगरानी की सुविधा के लिए छह बोरवेल, छह वाटर होल, अठारह बाड़े और चार वॉच टावर बनाए जाएंगे। निगरानी के उद्देश्य से 30 कैमरा ट्रेप भी लगाए जाएंगे।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

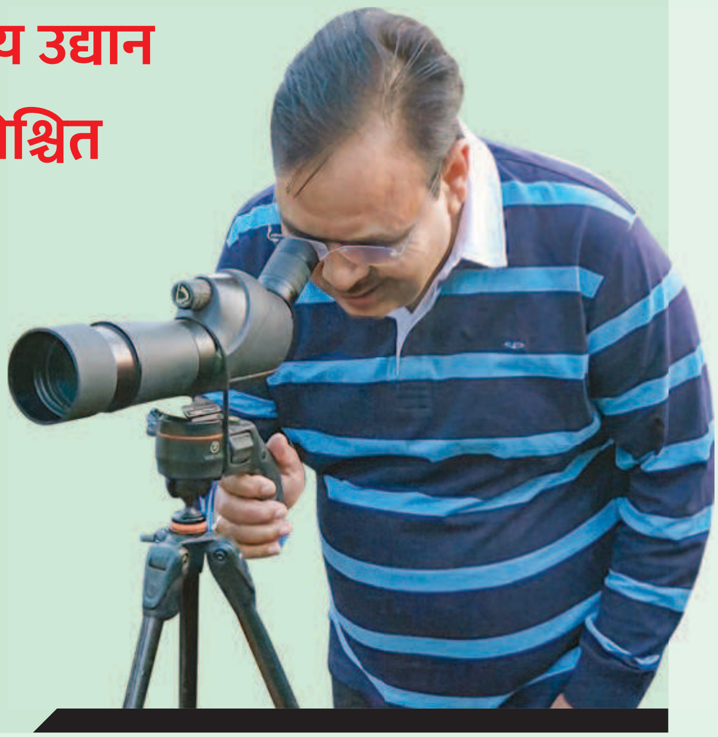

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मार्च माह में भरतपुर दौरे के दौरान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण किया। उन्होंने उद्यान में पक्षी व्यू प्वाइंट तक जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के साथ पैदल भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों की प्रजाति की विविधता के लिए देश और विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, इसलिए जिला प्रशासन यहां आने वाले पर्यटकों के लिए संचालित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे। श्री शर्मा ने राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी व्यू प्वाइंट पर केवलादेव शिव मंदिर में दर्शन भी किए।

आओ बचाएं
प्रकृति के नन्हे संदेशवाहक

- **अंजलिका पंवार,** सहायक जनसंपर्क अधिकारी

आँधी आई ज़ोर शोर से,
डालें टूटी हैं झकोर से।
उड़ा घोंसला अंडे फूटे,
किससे दुख की बात कहेगी!
अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी?

हमने खोला अलमारी को,
बुला रहे हैं बेचारी को।
पर वो चीं-चीं कर्राती है
घर में तो वो नहीं रहेगी!

घर में पेड़ कहाँ से लाएँ,
कैसे यह घोंसला बनाएँ!
कैसे फूटे अंडे जोड़ें,
किससे यह सब बात कहेगी!
अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी?

- महादेवी वर्मा

कुछ समय पहले की ही बात लगती है, जब सुबह होते ही नन्हीं सी गौरैया की चहचहाहट कानों में रस घोल देती थी। कभी खेतों में मंडराते हुए, तो कभी चोंच में तिनके दबाए अपने छोटे से घर को सजाते हुए ये हमें अक्सर दिख जाया करती थी। गौरैया, सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारे बचपन की मीठी यादों का हिस्सा भी रही है। यह पक्षी हमारे घरों और जीवन से इस कदर जुड़ा हुआ था कि लोक कथाओं और गीतों में भी इसका उल्लेख मिलता रहा है। लेकिन अफसोस, आज यह प्यारा पक्षी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है। गौरैया का पारिस्थितिकी तंत्र में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। यह छोटे-छोटे कीट-पतंगों को खाकर

प्राकृतिक कीट नियंत्रण में मदद करती है और पौधों के बीजों के प्रसार में सहायक होती है, जिससे हरियाली बढ़ती है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और बदलती जीवनशैली के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। आधुनिक इमारतों और कंक्रीट के जंगलों ने इनके घोंसले बनाने की जगह छीन ली है। पहले पुराने घरों, छज्जों और खपरैलों में इन्हें बसेरा मिल जाता था, लेकिन अब इनके लिए सुरक्षित ठिकाने नहीं रहे। भोजन की भी भारी कमी हो गई है, क्योंकि पहले गांवों और शहरों में खुले दाने रखना आम बात थी, लेकिन अब यह परंपरा धीरे-धीरे खत्म हो रही है। इसके अलावा, खेतों में कीटनाशकों और रसायनों के बढ़ते उपयोग से उनके प्राकृतिक आहार छोटे कीड़े-मकोड़े नष्ट हो रहे हैं। इससे उनके प्रजनन चक्र और अंडों पर बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन भी इनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है।

बढ़ता प्रदूषण, शोरगुल और प्लास्टिक कचरे के कारण ये मासूम पक्षी धीरे-धीरे हमारे पर्यावरण से गायब हो रहे हैं। अचानक बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग ने भी इनके जीवन को कठिन बना दिया है। अगर जल्द ही इनकी रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं जब गौरैया सिर्फ किताबों में ही रह जाएगी।गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ष 2010 में 'द नेचर फॉरएवर सोसाइटी' की गई पहल पर 'विश्व गौरैया दिवस' मनाने की शुरुआत की गई। हर साल 20 मार्च को यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें इन नन्हें पंछियों के लिए कुछ करने की जरूरत है। इस दिशा में हम छोटे-छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे अपने घरों और बगीचों में दाना-पानी रखना, लकड़ी या मिट्टी के छोटे घोंसले लगाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना।

हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैला सकते हैं और अपने आस-पास के लोगों को गौरैया संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस प्यारे पक्षी को बचाने के लिए आगे आएं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम एक पक्षी को बचाते हैं, तो हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में योगदान देते हैं। आइए, मिलकर गौरैया को फिर से हमारे आंगन और छतों पर चहचहाने का मौका दें। अगर हम आज प्रयास नहीं करेंगे, तो शायद कल यह चहचहाहट हमें कभी सुनाई ही न दे!

Bhajanlal Sharma
@BhajanlalBjp

आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि गौरैया जैसे छोटे-छोटे पक्षियों के संरक्षण और उनके आवास की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

8:12 am · 20 Mar 25

50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने 'मिशन हरियाळो राजस्थान' के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए गए तथा बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमारी संस्कृति में पेड़, प्रकृति एवं पहाड़ों की पूजा की जाती है तथा राजस्थान का पर्यावरण संरक्षण से पुराना नाता रहा है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि हम वनों को बचाने और अपनी जैव-विविधता को संरक्षित करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा-भरा और स्वस्थ राजस्थान बनाने का संकल्प लें।

रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल को बढ़ावा दे रही राज्य सरकार

श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी सरकार थ्री आर यानी रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल को बढ़ावा देकर कचरे के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने बजट 2025-26 में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इन्सेंटिव स्कीम 2025 की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरित आवरण में कृषि वानिकी की इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए हमारी सरकार राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति ला रही है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण एवं विस्तार हेतु "एक जिला एक प्रजाति" कार्यक्रम, सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना, वन रक्षकों की भर्ती जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही, हमारी सरकार द्वारा ग्रासलैंड के महत्व को समझते हुए राज्य में वृहद स्तर पर ग्रासलैंड संरक्षण एवं विकास के कार्य एवं घड़ियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है।

प्रदेशवासियों को मिली इन परियोजनाओं की सौगात

श्री शर्मा ने इस अवसर पर वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यो में पारदर्शिता लाने हेतु नवीनतम आईटी तकनीक के उपयोग से विकसित 'डिजी-वन-फोरेस्ट स्टैक' एप का शुभारम्भ किया, जो कि देशभर का पहला डिजिटल फोरेस्ट स्टैक है। साथ ही, उन्होंने सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर व

नाहरगढ़ बायोलोजिकल पार्क में गोल्फ कार्ट सुविधा को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन (सीआरईएसईपी) के लोगो का अनावरण तथा वन प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान का रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वनमित्रों को किट वितरित किए तथा वन विभाग में कार्यरत महिला कार्मिकों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया तथा गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जगमगाया राजस्थान...

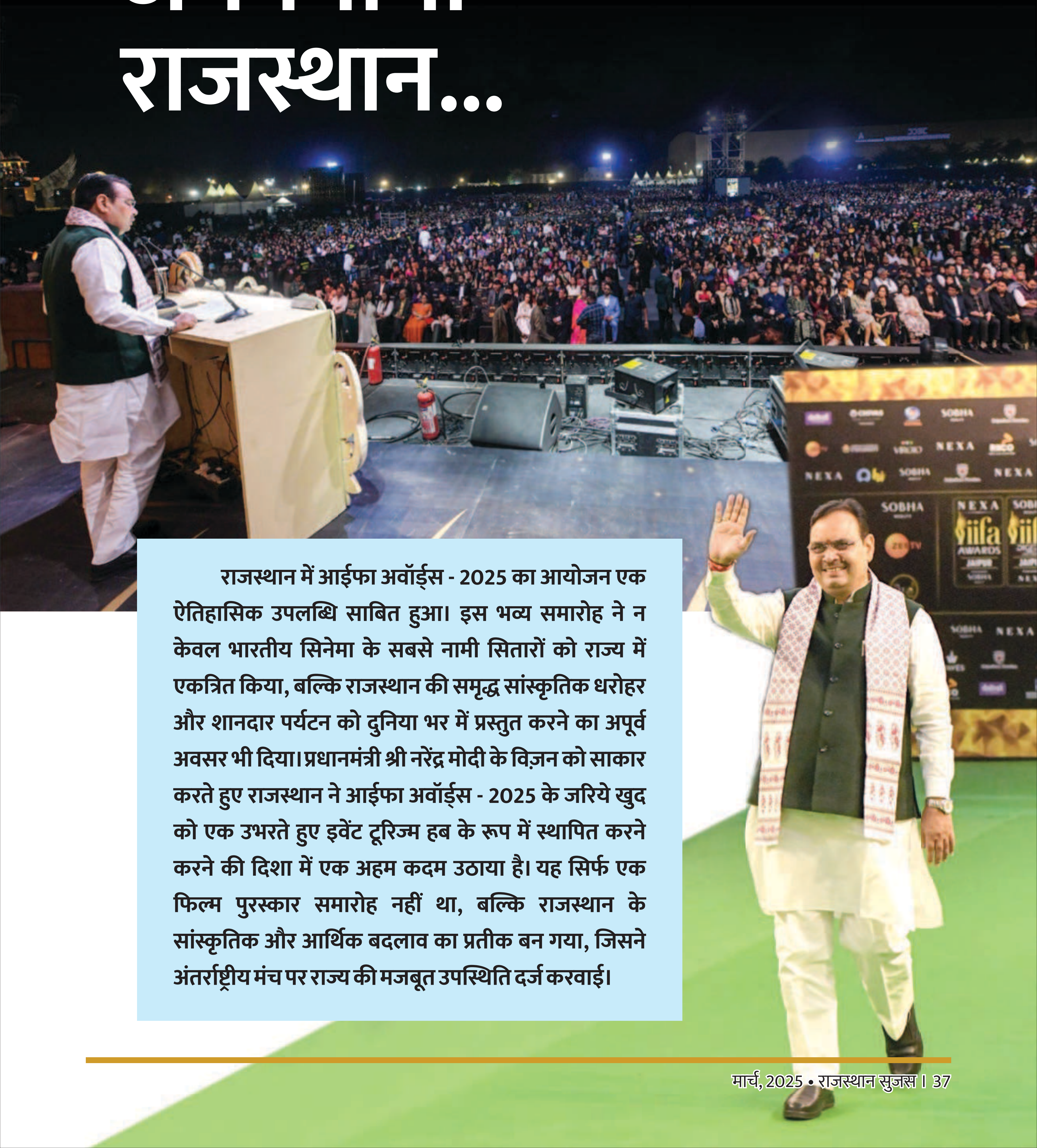

राजस्थान में आईफा अवॉर्ड्स - 2025 का आयोजन एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ। इस भव्य समारोह ने न केवल भारतीय सिनेमा के सबसे नामी सितारों को राज्य में एकत्रित किया, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और शानदार पर्यटन को दुनिया भर में प्रस्तुत करने का अपूर्व अवसर भी दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न को साकार करते हुए राजस्थान ने आईफा अवॉर्ड्स - 2025 के जरिये खुद को एक उभरते हुए इवेंट टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह सिर्फ एक फिल्म पुरस्कार समारोह नहीं था, बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक बन गया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य की मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई।

जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 8 व 9 मार्च को आईफा अवॉर्ड्स सिल्वर जुबली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आईफा अवार्ड्स समारोह के सिल्वर जुबली आयोजन के साथ ही जयपुर न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, और अबुधाबी जैसे उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां आईफा का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमारे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया भर में एक नई पहचान देगा।

श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का एक प्रमुख केंद्र है। यहां इतिहास भी है और धरोहर भी है। ट्रैवल्स और टूरिज्म सेक्टर को जो चाहिए, वह सब राजस्थान में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती भारतीय और वैश्विक सिनेमा के लिए शूटिंग का हमेशा से पसंदीदा स्थान रही है। यहां की विविधता इस प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए और भी आकर्षक बनाती है। उन्होंने फिल्म जगत से जुडी सभी हस्तियों को राजस्थान में अधिक से अधिक शूटिंग करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि दुनियाभर में राजस्थान ऐतिहासिक किलों, महलों के लिए प्रसिद्ध है। इनके हर पत्थर में शूरवीरों की गाथायें हैं। यहां चितौड़गढ़ का दुर्ग, कुम्भलगढ़ दुर्ग, महाराणा प्रताप के उदयपुर का किला, आमेर किला, सवाईमाधोपुर का रणथम्भौर दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का सोनार किला दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

धार्मिक पर्यटन के लिए राजस्थान आते है देश-दुनिया से पर्यटक

श्री शर्मा ने कहा कि देश दुनिया के करोड़ों लोग राजस्थान में धार्मिक पर्यटन के लिए भी आते हैं। यहां के विभिन्न मन्दिर, देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केन्द्र हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान को प्रकृति का भी बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ है, जैसलमेर धोरों की धरती है, तो उदयपुर झीलों की नगरी है और माउण्ट आबू पहाडों की रानी है। हमारा जयपुर पिंकसिटी है, तो जोधपुर ब्लू सिटी है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियां सुनहरे इतिहास की साक्षी हैं और हमारे यहां के तीज-त्यौहार हमारी लोक संस्कृति की पहचान हैं।

'पधारो म्हारे देश'

नोवोटल कन्वेंशन सेंटर में आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे गौरवशाली राज्य की राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड (आईफा) का सिल्वर जुबली आयोजन होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आईफा केवल एक अवॉर्ड समारोह नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा और संस्कृति के वैश्विक विस्तार का प्रतीक है, जिससे राजस्थान को अंतरराष्ट्रीय फिल्म और मनोरंजन उद्योग में नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक मनोरंजन और सांस्कृतिक उद्योग का केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। आईफा का यह आयोजन उसी विजन का एक सशक्त प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि आईफा का आयोजन राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग स्थल, डेस्टिनेशन वेडिंग और लाइव इवेंट्स के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। साथ ही, राजस्थान में कॉन्सर्ट टूरिज्म के नए आयाम भी खुलेंगे।

सेलेब्रिटीज के लिए राजस्थान पसंदीदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सदियों से अपनी भव्यता, शाही विरासत और राजसी आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। हर साल हजारों विवाह यहां के भव्य महलों, किलों, हवेलियों और होटलों में होते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेलेब्रिटी भी राजस्थान को अपनी ड्रीम वेडिंग के लिए चुन

लाइट, कैमरा - राजस्थान

रहे हैं। देश की 75 प्रतिशत हेरिटेज प्रॉपर्टी यहां है, जो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे आकर्षक स्थल बनाती हैं। श्री शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में विवाह एवं ऐसे अन्य भव्य आयोजनों से होटल, पर्यटन, स्थानीय कारीगरों और पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को लाभ हुआ है।

प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक समृद्ध क्षेत्र निर्माता-निर्देशकों की विशेष पसंद

श्री शर्मा ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान में 61 वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन फिल्म, फीचर फिल्म, टीवी शो, टीवी सीरियल और म्यूजिकल वीडियो की शूटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर और शेखावाटी जैसे क्षेत्र निर्माता-निर्देशकों की विशेष पसंद बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की अनुपम संभावनाएं फिल्म निर्माण के लिए इसे आदर्श गंतव्य बनाती हैं। यहां की सुनहरी रेत, विशाल किले, शांत झीलें, वन्य जीव अभयारण्य, अरावली के पहाड़, चम्बल का किनारा और जीवंत ग्रामीण जीवन फिल्मकारों के अपने सपनों को साकार करने के लिए एक कैनवास प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बिना बॉलीवुड की कल्पना नहीं की जा सकती है।

राजस्थान का सड़क, रेल व हवाई मार्ग मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सड़क, रेल, और हवाई मार्ग से देश और दुनिया से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर जैसे शहर भी हवाई मार्ग से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के राजस्थान पर विशेष स्नेह के कारण यहां से देश के हर कोने के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। राजस्थान का समृद्ध सड़क तंत्र राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

बॉलीवुड के कलाकार राजस्थान की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर

श्री शर्मा ने कहा कि बॉलीवुड के कलाकार राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे जब राजस्थान की धरती पर आते हैं, तब 'धरती धोरां री' और 'पधारो म्हारे देश' की संस्कृति को दुनियाभर में लेकर जाते हैं। यहां की सड़कें न केवल शहरों को जोड़ती हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक फिल्म निर्माण की राह आसान बनाती हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण को सरल बनाने के लिए राजस्थान सरकार की सिंगल विंडो सुविधा एक वरदान है। यहां ऑनलाइन परमिशन सिस्टम के जरिए सभी क्लीयरेंस 15 दिनों के भीतर जारी हो जाते हैं। वन्य जीवन पर आधारित फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के लिए राजस्थान एक स्वर्ग है। जवाई और झालाना में लेपर्ड की मौजूदगी, रणथंभोर और सरिस्का जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जैव-विविधता को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत के अतिथियों से अनुरोध करते हुए कहा कि राजस्थान में फिल्म बनाना केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जहाँ प्रकृति, इतिहास और संस्कृति आपके हर दृश्य को अमर कर देती है। राजस्थान की धरती आपको बुला रही है। उन्होंने आइफा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान की मेहमान नवाजी सभी को पसंद आती है।

आईफा गार्डन

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से प्रेरित होकर जयपुर में आईफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की एक नई पहल की गई है। यहां आईफा अवॉर्ड जीतने वाले कलाकारों और उनकी मां के नाम पर पौधे लगाए गए हैं। इस गार्डन में लगाए जाने वाले 15 हजार पौधे इस समारोह को चिरस्थायी एवं यादगार बनाएंगे।

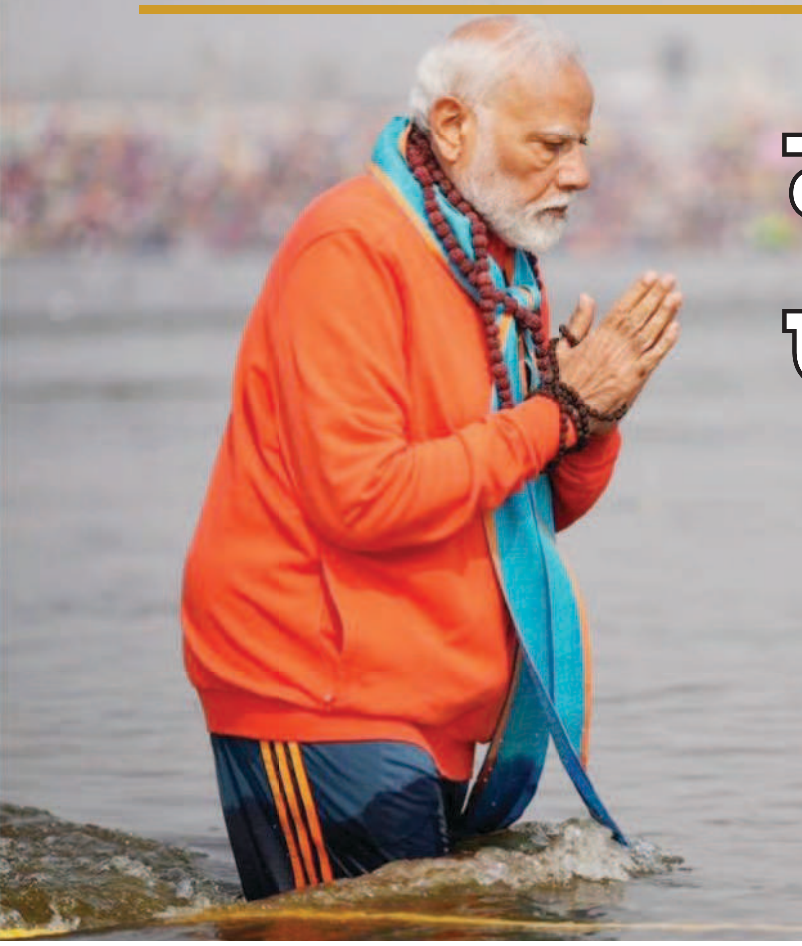

महाकुंभ के पंच महा-अमृत

– **विवेक जादौन,** उप निदेशक

श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परम् प्रमाणं।
यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः।।

श्रुतियां प्रमाण हैं, स्मृतियां प्रमाण हैं और सबसे अधिक पुराण प्रमाण हैं। गंगा तथा यमुना जिसकी महत्ता की स्वयं प्रमाण हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो।।

पुण्य सलिला गंगा, सूर्यतनया यमुना और ज्ञानप्रदायिनी पौराणिक सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज की महिमा स्वयंसिद्ध व स्वयंप्रमाणित है। ऐसे अति पवित्र एवं प्रगाढ़ आस्था के केन्द्र त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला विराट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है महाकुम्भ। कहा जाता है कि एक बार कुम्भ स्नान करने से एक हजार अश्वमेध यज्ञ, एक सौ वाजपेय यज्ञ, और पृथ्वी की एक लाख परिक्रमा करने का फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस में भगवान श्रीराम द्वारा त्रिवेणी दर्शन और स्नान के बारे में लिखा है-

एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी।।
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाबिधि तीरथ देवा।।

पौराणिक आख्यानों के अनुसार महाकुम्भ में देवों और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ निकला था। इस दिव्य अमृत कुंभ के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच हुए संघर्ष के दौरान अमृत की चार बूंदें धरती पर गिरी थीं। उन चारों स्थानों पर ही क्रमवार 12 वर्ष के अंतराल से कुंभ मेला लगता है। 12 कुंभ के बाद 144वें वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होता है। इस सहस्त्राब्दी का प्रथम महाकुंभ पौष पूर्णिमा (13 जनवरी 2025) से महाशिवरात्रि (26 फरवरी 2025) तक प्रयागराज की पावन धरती पर आयोजित किया गया। महाकुम्भ की दिव्यता, भव्यता और पवित्रता का तो कहना ही क्या। 45 दिनों तक देश-विदेश से आए कोटि-कोटि श्रद्धालुओं का महासागर पूरे श्रद्धा भाव से संगम में डुबकियां लगाता रहा। जिसने भी डुबकी लगाई, उसी ने कहा कि महाकुम्भ जैसा दूसरा कुछ इस धरती पर देखा ही नहीं। इस भव्य आयोजन के फलित न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्मावलम्बियों को ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि महाकुम्भ से निकला अमृत राष्ट्र के संकल्पों की सिद्धि का मजबूत माध्यम बनेगा। आइए, जानते हैं उन पंच महा-अमृत के बारे में, जो महाकुम्भ में आस्था के पुण्य मंथन से हमें मिले हैं-

मेगा मैनेजमेंट सक्सेस स्टोरी

महाकुम्भ-2025 ऐसा आयोजन रहा, जिसके आकार और परिमाण का दूसरा आयोजन विश्व में देखने को नहीं मिलता। दो तरफ से गंगा- यमुना

और तीसरी तरफ प्रयाग नगर से घिरे 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गंगा और यमुना के किनारे एक पूरी कुम्भनगरी बसाई गई। केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करीब 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय कर महाकुंभ की दृष्टि से विकास कार्य और व्यवस्थाएं की गईं। एक अस्थायी नगर के रूप में 2 लाख टेंट, 5 लाख पार्किंग स्थान और 25 हजार फ्री टेन्ट की एक टेन्ट सिटी विकसित की गई, जिसमें 400 किलोमीटर अस्थायी सड़कों, 30 पंटून पुल, 1,250 किलोमीटर लम्बी जल आपूर्ति पाइपलाइन, 366 किलोमीटर लम्बी ट्रांसमिशन केबल, 67,000 स्ट्रीट लाइटें, 2,750 सीसीटीवी कैमरे, डेढ़ लाख शौचालय, 8 स्थायी घाट सहित 41 स्नान घाटों का आधारभूत ढांचा तैयार किया गया।

महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए महाकुम्भ नगर नाम से चार तहसीलों का नया अस्थायी जिला घोषित किया गया। इस जिले में जिला मजिस्ट्रेट सहित दो आईएएस, तीन एडीएम और 25 एसडीएम नियुक्त किए गए। मेले में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की दृष्टि से केन्द्र एवं राज्य पुलिस बलों के 40 हजार जवान, 2 हजार अग्निशमन कर्मी तैनात किए गए। मेला क्षेत्र को 10 जोन, 25 सेक्टर, 3 तैरते हुए जल पुलिस थानों सहित 56 पुलिस थानों और 155 चौकियों में बांट कर 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। 15 हजार स्वच्छता कर्मियों ने दिन-रात काम कर प्रतिदिन 400 टन कचरा एकत्र करते हुए कुम्भ क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा।

सक्षम नेतृत्व, कुशल नियोजन, आधारभूत ढांचे के निर्माण, संसाधन और संकट प्रबंधन और प्रौद्योगिकीय एवं एआई नवाचारों की बदौलत 15 लाख जनसंख्या वाले प्रयागराज शहर ने मेला अवधि के दौरान 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं की कुशलतापूर्वक मेजबानी की। 2019 के अर्ध कुंभ में आए 25 करोड़ श्रद्धालुओं की तुलना में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि थी।

इन विशिष्टताओं के कारण महाकुम्भ का महा-आयोजन विश्वभर के प्रबन्ध संस्थानों, कॉर्पोरेट घरानों और शोधार्थियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा लाइव मैनेजमेंट केस स्टडी बन गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकॉनमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एम्स नई दिल्ली, आआईएम अहमदाबाद, बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, कानपुर सहित दो दर्जन से अधिक संस्थानों के प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर और विद्यार्थी महाकुम्भ मेला क्षेत्र में डेरा डाले रहे। महाकुम्भ के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा रणनीति, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन, खाद्य प्रबंधन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अस्थायी नगरीय नियोजन एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अध्ययन के बारे में इन संस्थानों की ओर से औपचारिक आवेदन सरकार को प्राप्त हुए।

राष्ट्रीय चेतना का जागरण

महाकुंभ एक प्रकार से भारत के विराट स्वरूप का दिग्दर्शन था। इस आयोजन में प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़, मौनी अमावस्या पर 5 करोड़, बसंत पंचमी पर 2.33 करोड़, माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ और महाशिवरात्रि पर 1.3 करोड़ लोगों ने संगम और उसके विभिन्न घाटों पर डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर तो प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बडी आबादी वाला नगर

बन गया। दुनिया के लिए हैरत की बात यह थी कि ये सभी लोग बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के ही स्वतः स्फूर्त भाव से महाकुम्भ में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में, यह जनता-जनार्दन का, जनता-जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता-जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। इस आयोजन ने देश की सामूहिक चेतना का सामर्थ्य दुनिया को बताया, जिसका परिणाम यह रहा कि महाकुम्भ पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र बना और 183 देशों से श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगाने आए।

भेदभाव-मुक्त समाज

जात पात पूछे नाहि कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संत शिरोमणि रविदास के इन भावों को चरितार्थ करते हुए प्रयागराज महाकुंभ में जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषा की सीमाएं मिट गईं। स्त्री-पुरुष, बच्चे-बुजुर्ग, धनाढ्य-निर्धन, शहरी-ग्रामीण सभी एक मन, एक भाव से अनादिकाल से चली आ रही आध्यात्मिक परम्परा से जुड़ने के लिए साथ-साथ चलते, साथ-साथ संगम स्नान करते और हर-हर गंगे का जयकारा लगाते नजर आए। महाकुम्भ 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को और मजबूत करते हुए इस बात का प्रमाण बना कि भारत की संस्कृति सबको जोड़ने वाली है। जेन वाय, जेन ज़ी के रूप में पहचान रखने वाले सहस्त्राब्दी युवा जिस सहज समर्पण और आस्था के साथ महाकुम्भ में आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति करने पहुंचे, उससे आश्वस्ति हुई कि भाषा, भेष और परिवेश में आ रहे बदलाव के बावजूद युवा पीढ़ी संस्कारों से तनिक भी विचलित नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि हमारी एकता का अमृत महाकुंभ से निकला सबसे बड़ा अमृत है।

सफल सांस्कृतिक कूटनीति

यूनेस्को द्वारा 2017 में कुंभ मेले को एक सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। प्रयागराज महाकुम्भ में तो भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर का लोहा सारी दुनिया ने माना। भारत ने जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सम्पूर्ण मानवता का कुंभनगरी में स्वागत किया। महाकुम्भ के माध्यम से भारत ने धार्मिक, नस्लीय और क्षेत्रीय

अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहे विश्व को समानता, समरसता, स्थिरता और सहिष्णुता का संदेश दिया। राष्ट्राध्यक्षों सहित 77 देशों के राजनयिकों और उनके परिजनों ने महाकुम्भ में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाई। सनातन मूल्यों में आस्था रखने वाले विश्वभर में फैले लोगों को इस आयोजन ने एक सूत्र में बांधने का काम किया। महाकुंभ केवल स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह धर्म, अध्यात्म, नीति, दर्शन, संस्कृति और परंपराओं पर वैश्विक विमर्श का केन्द्र बनकर भी उभरा। विदेशी मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, और व्लॉगर्स भी महाकुंभ में साधु-संतों, प्रतिष्ठितजनों, विद्वानों और श्रद्धालुओं की गतिविधियों के पल-पल को कैद करते नजर आए।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को संजीवनी

महाकुंभ ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने से एक बड़ी पॉप-अप इकॉनमी पनपी, जिससे होटल, परिवहन, भोजन, हस्तशिल्प और खुदरा स्थानीय व्यवसायों को सीधा लाभ हुआ और स्थानीय रोजगार के लाखों अवसर सृजित हुए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आकलन के अनुसार इस बार महाकुंभ में आर्थिक गतिविधियों से 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।

भारत में धार्मिक-आध्यात्मिक पर्यटन की विपुल संभावनाएं महाकुम्भ के माध्यम से खुलकर सामने आईं। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में से बहुत सारे श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के बाद दर्शन के लिए अयोध्या में श्रीराम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और चित्रकूट भी पहुंचे। इस तरह वाराणसी-प्रयागराज-अयोध्या-चित्रकूट धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा सर्किट बनकर उभरा। महाकुम्भ के जैसे बड़ा धार्मिक आयोजन के सकारात्मक आर्थिक प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में तेजी देखी गई।

महाकुम्भ में प्रयागराज स्थित राजस्थान मण्डप में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।

महाकुंभ पथिकों के पाथेय, आश्रय और विश्राम का केन्द्र बिन्दु रहा राजस्थान मण्डप

"अतिथि देवो भवः" की परंपरा राजस्थान की संस्कृति की पहचान है। जब शासन जनता की भलाई और सुख-शांति के लिए समर्पित होता है, तब ही सच्चे अर्थों में रामराज्य की परिकल्पना पूरी होती है। रामराज्य का मतलब सिर्फ राज्य को आदर्श शासन नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है, जहाँ आम जनता को सुरक्षा, स्नेह और संतुष्टि मिले। राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस प्रजावत्सलता के भाव को साकार किया है। मुख्यमंत्री जी की पहल पर, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में स्थापित राजस्थान मण्डप, इसी वत्सल भाव का प्रतीक बनकर सामने आया है।

राजस्थान मण्डप

श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी, किया आराम, राम और राज का आज भी कर रहे गुणगान

– **डॉ. आशुराज आनंद,** जनसंपर्क अधिकारी

– **सिकन्दर राज जायसवाल,** सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

सदी का महाकुंभ मेला तीर्थराज प्रयाग में सम्पन्न हुआ, जिसमें देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के सरोवर में स्नान किया। इस भव्य आयोजन में राजस्थान के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर, राज्य के तीर्थयात्रियों की यात्रा को और अधिक सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान मंडप की स्थापना की गई। इस मंडप में श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा गया, ताकि उनकी यात्रा न केवल आरामदायक हो, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित और यादगार बन सके।

आस्था और सेवा का प्रतीक

नागवासुकी मंदिर के पास स्थित सेक्टर 7 के मेलाक्षेत्र में राजस्थान मंडप में न केवल राजस्थानवासियों, बल्कि अन्य प्रदेशों और देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं का आस्था और सेवा भाव से सत्कार किया गया। मंडप में श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए आश्रय, ओढ़ने के लिए वस्त्र, और भोजन-प्रसादी की व्यवस्था की गई। ठंडी रातों में विशेष रूप से वृद्धजन, माताएं, बहनें, बच्चे और सभी श्रद्धालुओं को सर्व धर्म समभाव और सहिष्णुता के साथ आश्रय दिया गया। राजस्थान मंडप ने "पधारो म्हारे देश" की संस्कृति को जीवित रखते हुए राजस्थानी आतिथ्य की परंपरा को साकार किया।

सौंदर्य और भव्यता

महाकुंभ में अन्य राज्यों के मंडपों के बीच राजस्थान मंडप की सौंदर्य और भव्यता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मंडप में राजस्थानी संस्कृति से परिपूर्ण संरचनाएं, कलात्मक सजावट और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कटआउट्स के साथ बने सेल्फी प्वाइंट ने एक अद्भुत माहौल तैयार किया। निरंतर चलने वाले आध्यात्मिक भजन-कीर्तन ने मंडप में एक दिव्य वातावरण का निर्माण किया।

प्रचार-प्रसार और सूचना सामग्री का वितरण

राजस्थान मंडप में राज्य की विकासात्मक नीतियों, उपलब्धियों, जनकल्याणकारी फैसलों और प्रगतिशील कार्यों की जानकारी से भरे बुकलेट्स, कैलेंडर, मैगज़ीन और सर्वहितकारी बजट पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। इन सामग्रियों के माध्यम से आगंतुकों को राजस्थान सरकार की योजनाओं और कार्यों के बारे में जागरूक किया गया। मंडप में गुलाबी रोशनी और विशिष्ट शिल्प-स्थापत्य के सुंदर चित्रों और सजावट ने इसे विशेष आकर्षण का केंद्र बना दिया।

सहयोग - समन्वय की मिसाल

मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के सहयोग से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, देवस्थान विभाग, पुलिस महकमें, परिवहन विभाग, आयोजना विभाग आदि ने सतत समन्वय स्थापित करते हुए यात्रियों के लिए आवागमन, सुरक्षा, भोजन-प्रसादी, वाहनों की पार्किंग, प्रदेश की प्रगति व उपलब्धियों की जानकारी, खोया-पाया केन्द्रों से समन्वयन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क दवा-इलाज आदि की भी पर्याप्त व समुचित व्यवस्था करवाई।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 'राजस्थान मंडप' में दी जा रही सेवाओं की सुनिश्चितता की जानकारी निरंतर रूप से लेते रहे और उन्होंने ने अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान 'राजस्थान मंडप' में श्रद्धालुओं को भोजन भी परोसा।

होली की उमंग

संग फाग और रंग

होली पूजन, होलिका दहन व स्नेह मिलन समारोह

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने होली के अवसर पर सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर परिवारजनों के साथ श्री राज राजेश्वरी मंदिर प्रागंण में विधिवत रूप से होली पूजन किया। उसके बाद मंत्रोच्चार के बीच होलिका दहन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में मुख्यमंत्री ने आमजन के साथ आत्मीय मुलाकात कर फूलों व प्राकृतिक रंगों से होली खेली।

फूलों की होली, हर्षोल्लास का रंग

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने होली पर पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने आमजन पर पुष्प वर्षा कर उनके साथ फूलों की होली खेली, चंग की थाप पर सभी ने उमंग और उत्साह से पर्व का आनन्द लिया। श्री शर्मा ने पूंछरी का लौठा में मुकुट मुखारविंद पर श्रीगिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया। होली महोत्सव में श्रीनाथ जी मंदिर कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा मयूर नृत्य सहित विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। हर कोई श्री कृष्ण की भक्ति में झूमता नजर आया।

श्री गलताजी तीर्थ फागोत्सव
अवधपुरी और ब्रज दर्शन एक साथ

श्री गलताजी तीर्थ में पिछले दिनों हुए ब्रज-अवध फागोत्सव में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि श्री गलताजी तीर्थ में फागोत्सव का आयोजन विशिष्ट है।

उन्होंने कहा, श्री गलताजी में दिव्यता व भव्यता की अनुभूति होती है। यहां स्थित भगवान श्रीराम, श्रीविष्णु और हनुमानजी के मंदिर अवधपुरी और ब्रज के एक साथ होने की अनुभूति देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के साथ-साथ हमारी गौरवशाली विरासत का संरक्षण भी हो रहा है। राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थलों का विकास एवं संरक्षण कार्य प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। मुख्यमंत्री ने सीताराम जी मंदिर और ज्ञान गोपाल जी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और गौ सेवा भी की। उन्होंने फागोत्सव में भजनों-गीतों का श्रवण किया तथा दीप महाआरती में शामिल हुए।

राजस्थान में होगा बुलेट ट्रेन, अन्य हाई स्पीड इंजन और डिब्बों का परीक्षण

जयपुर के पास आकार ले रहा देश का पहला आरडीएसओ डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक रेलवे के आधुनिकीकरण में साबित होगा मील का पत्थर

कैप्टन शशि किरण - मुख्य जन संपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे

देश में बुलेट ट्रेन जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए दमदार, अद्यतन और सुरक्षित ट्रैक निर्माण और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में राजस्थान में देश का पहला और विश्व का संभवत: सबसे बड़ा अत्याधुनिक परीक्षण स्थल जयपुर से 70 किलोमीटर दूर गुढ़ा-ठठाना मीठड़ी के बीच आकार ले रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में आधारभूत संरचना के रूप में भारतीय रेलवे के विकास की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रदेश, देश और दुनियाभर में भारतीय रेलवे की यह प्रगति अब तेजी से धरातल पर नजर आ रही है। रेलवे सेक्टर में निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेशन, विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सुदृढ़ता और इसके अन्य विविध पक्षों पर तीव्र गति से काम हो सके इसके लिए भारत सरकार ने कई कम्पनियों का निर्माण किया है और बजटीय व्यवस्था की है। भविष्य में बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेनें भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ते हुए शहरों और प्रदेशों की दूरियों को पाट सकें, इसके लिए पिछले कुछ समय से भारतीय रेलवे में ट्रेनों की गति पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आज वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें देश के कोने-कोने में दौड़ रही हैं और आमजन के बीच काफी लोकप्रिय हैं। देश में बुलेट ट्रेन के संचालन के लिए मुम्बई से अहमदाबाद के बीच कार्य तेजी से किया जा रहा है। बदलाव की इस बयार के साथ भविष्य में देश में तेज गति से दौड़ने वाली कई ट्रेनें देखने को मिलेंगी। हाई स्पीड ट्रेनों की अगवानी के लिए जरूरी है कि इस सफर को शत-प्रतिशत सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे के परीक्षण के तरीकों और ट्रेक सहित उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाए।

रेलवे द्वारा विगत समय में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ-साथ सुरक्षित रेल संचालन पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। संरक्षा को सुदृढ़ करने में रेलवे ट्रैक के अलावा रोलिंग स्टॉक (पटरी पर दौडने वाले डिब्बे व इंजन) की भी अहम भूमिका रहती है। रोलिंग स्टॉक को उपयोग में लाने से पूर्व इसका व्यापक और गहनता के साथ परीक्षण किया जाना होता है, तभी यह सुरक्षा की कसौटी पर खरा उतर सकता है। रोलिंग स्टॉक के परीक्षण की सुविधा को विकसित करने के लिए राजस्थान में देश के पहले डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक निर्माण की कार्ययोजना बनाकर इसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

देश के प्रथम डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक की स्थापना से देश के हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के परीक्षणों में नए आयाम स्थापित होंगे और रेलवे के आधुनिकता की ओर बढ़ने की दिशा में यह टेस्ट ट्रैक मील का पत्थर सिद्ध होंगे। इन परीक्षणों के माध्यम से रेलवे संसाधनों को व्यापक और पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग में लेने में सक्षम होगा।

कुल 64 किलोमीटर का है डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक

भारतीय रेलवे द्वारा देश में हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण के लिए देश के इस प्रथम आरडीएसओ (रिसर्च, डिजाइन एण्ड स्टेण्डर्ड ऑर्गेनाइजेशन) डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान के जोधपुर डिवीजन (जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर) में गुढा-ठठाना मीठड़ी के बीच 64 किलोमीटर में किया जा रहा है। यह कार्य 2 चरणों में स्वीकृत किया गया है। फेज 1 का कार्य दिसम्बर 2018 में तथा फेज 2 का कार्य नवम्बर 2021 में स्वीकृत किया गया। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 967 करोड़ रुपये है। इस टेस्ट ट्रेक के निर्माण से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रकार के रोजगार का सृजन होगा तथा भारत रेलवे परिवहन में उन्नत तकनीक के उपयोग में अग्रसर होगा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूती मिलेगी।

220 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रणाली, दिसम्बर तक पूरा होगा काम

इस डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक में 220 किमी प्रति घंटे की ओएचई (ओवर हैड

राजस्थान के गुढ़ा-ठठाना मीठड़ी के मध्य 64 किलोमीटर लम्बाई का आरडीएसओ डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक।

इक्विपमेंट) और सभी तरह की आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली प्रदान की जा रही है। इस परियोजना का काम चार चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 19.8 किलोमीटर, दूसरे में 15 किलोमीटर, तीसरे में 2.7 किलोमीटर एवं चौथे में 26.06 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाएगा। पहले व दूसरा चरण का काम पूर्ण हो चुका है। तीसरा एवं चौथा चरण आंशिक रूप से पूर्ण हो चुका है तथा बाकी कार्य प्रगति पर है। डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक के निर्माण में 7 बड़े पुल, 130 छोटे पुल व 4 स्टेशन (गुढ़ा, जबड़ीनगर, नावां व मीठड़ी) सम्मिलित हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 35 किलोमीटर का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर 2025 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक परीक्षण के लिए विश्वस्तरीय तकनीक युक्त निर्माणाधीन ट्रैक

दुनियाभर में खास होगा राजस्थान का ट्रेक

इस डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक निर्माण के बाद भारत पहला ऐसा देश होगा जिसके पास यूआईसी-518 या ईएन-14363 के अनुसार रोलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक परीक्षण सुविधाएं होंगी। राजस्थान में बनने वाला यह डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक दुनिया भर में अलग तरह का ट्रैक होगा, क्योंकि वर्तमान में सभी जगह उपलब्ध अधिकांश टेस्ट ट्रैक की लम्बाई इससे कम है। राजस्थान में बनने वाले इस टेस्ट ट्रैक से भारतीय तकनीक को दुनियाभर में नई पहचान मिलेगी और नवाचार से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक, भारतीय रेलवे के भविष्य को तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेगा एवं यात्री संरक्षा को मजबूती देगा।"

डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक पर मानक मापदंडो के अनुरूप निर्माण कार्य

ट्रैक रेल की गति, सुरक्षा, सिग्नलिंग सहित कई परीक्षण में सक्षम

"इस टेस्ट ट्रैक पर दुनियाभर में निर्मित हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के परीक्षण की सुविधा विकसित की जाएगी। इस सुविधा से रेलवे में तकनीक व प्रौद्योगिकी को तेजी से आत्मसात करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा रोलिंग स्टॉक और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक क्षमता के उपयोग को आगे ले जाने में सहायक होगी। हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक और अन्य यंत्रों की व्यापक परीक्षण सुविधाएं, जिनमें गति परीक्षण, स्टेबिलिटी, सुरक्षा मापदंड, दुर्घटना प्रतिरोधक क्षमता, रोलिंग स्टॉक की गुणवत्ता इत्यादि के परीक्षण को इस परियोजना में विकसित किया जा रहा है। इस डेडीकेटेड टेस्ट ट्रैक में ट्रैक सामग्री, पुलों, टीआरडी उपकरण, सिग्नलिंग गियर और भू-तकनीकी अध्ययनों का परीक्षण भी सम्मिलित है।"

श्री अमिताभ,
महाप्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे

राज्य की समृद्धि, आत्म निर्भरता और विकास की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल

पंच गौरव-जिले की पंचमुखी पहचान

- **डॉ. सुदीप कुमावत,** सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

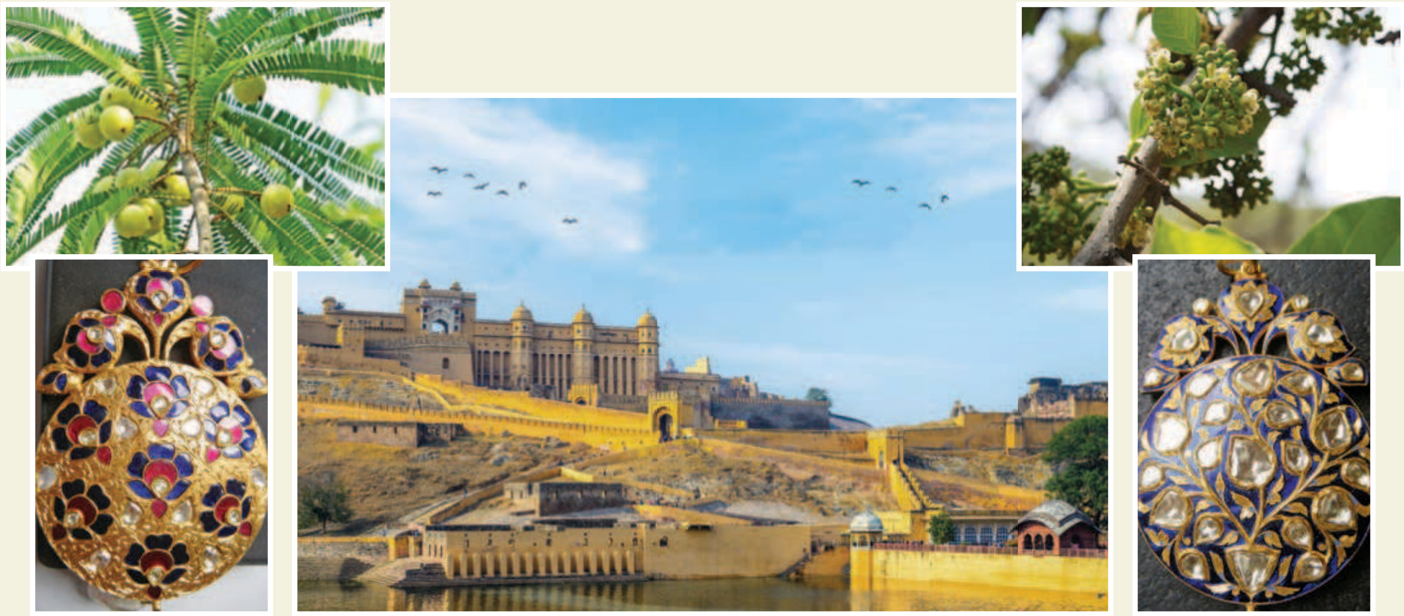

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य की भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में पंच गौरव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचानों, यथा वहां की उपज, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद, खनिज संपदा और पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर, उन्हें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाएगा।

प्रदेश की राजधानी जयपुर जिले में भी पंच गौरव कार्यक्रम में जिले की विशिष्ट पांच पहचानों को चिन्हित कर, इन्हें बढ़ावा देने के प्रयास वृहद स्तर पर प्रारम्भ कर दिए गए हैं। पंच गौरव कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित विषय विशेषज्ञों की समितियां गठित करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर, उनमें आवश्यक सुधार करने में सहायता मिलेगी और उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी।

जिले के पंच गौरव

जयपुर जिले के पंच-गौरव 1. एक जिला-एक उत्पाद : रत्नाभूषण, 2. एक जिला-एक उपज : आंवला, 3. एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति : लिसोड़ा, 4. एक जिला-एक खेल : कबड्डी एवं 5. एक जिला-एक पर्यटन स्थल : आमेर दुर्ग को चिन्हित किया गया है।

1. एक जिला-एक उत्पाद : रत्नाभूषण

जयपुर रंगीन रत्नों एवं आभूषण तथा कुंदन की मीनाकारी के लिए अपनी स्थापना के समय से ही विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहां कई पीढ़ियों से शिल्पकार परम्परागत रूप से इस व्यवसाय में लगे हैं। इसे और प्रोत्साहित करने व स्थानीय समुदाय को इससे जोड़ने के लिए जिला उद्योग विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिले में रत्नाभूषण से सम्बन्धित कार्यक्रमों में पंच-गौरव का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

2. एक जिला-एक उपज : आंवला

जयपुर के आंवला को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों की संगोष्ठियां, बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें किसानों को आंवला के बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आंवला की उपज को उचित लाभ और बाजार उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार और किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा।

3. एक जिला-एक वनस्पति प्रजाति : लिसोड़ा

वन विभाग द्वारा अपनी नर्सरियों में लिसोड़े के 50 हजार पौधे तैयार किए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत की नर्सरियों में भी आंवले और लिसोड़े के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा अमृता-निसोरा वाटिका बनाने की पहल की गई है। जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगरपालिका में आंवला और लिसोड़ा के 250-250 पौधे लगाने के लिए उपखण्ड अधिकारियों से भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

4. एक जिला-एक खेल : कबड्डी

जयपुर जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक

विकास के लिए हर शनिवार को सभी विद्यालयों में कबड्डी सहित अन्य खेलों का आयोजन शुरू किया है। 1760 राजस्व गांवों में से 761 गांवों में कबड्डी के मिट्टी मैदान बनाए जा रहे हैं और 337 गांवों में यह तैयार भी हो चुके हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक सिंथेटिक कबड्डी मैट मैदान भी तैयार किया जा रहा है। महिला दिवस 8 मार्च 2025 को ब्लॉक फागी, आमेर और मौजमाबाद में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कबड्डी मैच आयोजित किए गए।

5. एक जिला-एक पर्यटन स्थल : आमेर दुर्ग

आमेर दुर्ग को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनमें मुख्यतः हाथी की सवारी एवं लाइट एण्ड साउण्ड शो है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी टूर को बढ़ावा देना, सन सेट प्वाइंट, कपल फोटोशूट, वेडिंग फोटो साइट्स को विकसित करना, रॉयल फैमिली गेस्ट डिनर, रॉयल वेडिंग को बढ़ावा देना, मावठा झील को जलमहल के तर्ज पर विकसित करना, स्थानीय त्यौहारों/मेलों का आयोजन करवाना एवं हेली टूरिज्म/ड्रोन टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले कार्य किए जाना प्रस्तावित है।

जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन

पंच-गौरव के विकास के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला समन्वय समिति बनाई गई है, जिसमें उद्योग विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, खेल एवं युवा मामलात विभाग, पर्यटन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला कलक्टर द्वारा नामित राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी सदस्य हैं तथा संयुक्त, उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं। इस समिति को कार्ययोजना तैयार करने एवं हर तिमाही समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट और विभिन्न विभागों, निजी संगठनों तथा उद्योग संघों के सहयोग से पंच-गौरव कार्यक्रम को वित्त पोषित और विकसित किया जा रहा है।

एक ही दिन में 5 लाख से अधिक को किया जागरूक

पंच-गौरव को प्रोत्साहन के माध्यम से जिले को सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान देने के लिए जिला प्रशासन ने 26 जनवरी 2025 को 7615 विद्यालयों में पंच-गौरव के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 5 लाख विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों को पंच-गौरव के बारे में जानकारी दी गई।

“ राजस्थान को अपनी भौगोलिक विविधताओं, प्राकृतिक संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। राजस्थान के हर जिले की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, जो वहां की उपज, हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद, खनिज संपदा और पर्यटन स्थलों में परिलक्षित होती है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 'पंच-गौरव' कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम के तहत हर जिले में 'पंच-गौरव' के रूप में एक उत्पाद, एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक खेल और एक पर्यटन स्थल चिह्नित किया गया है। पंच-गौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले के लिए रत्नाभूषण को उत्पाद, आंवला को उपज, लिसोड़ा को वनस्पति प्रजाति, कबड्डी को खेल और आमेर दुर्ग को पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित किया गया है। मुझे विश्वास है कि पंच गौरव कार्यक्रम से आमजन के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर, कौशल उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि एवं विभिन्न क्षेत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। साथ ही हमारे संयुक्त प्रयासों से विकसित राजस्थान का सपना भी साकार होगा। ”

-मुख्यमंत्री

आवश्यक सूचना

फार्म-1
(नियम 3 देखिये)

1.	समाचार पत्रिका का नाम	:	राजस्थान सुजस
2.	समाचार पत्रिका की भाषा	:	हिन्दी
3.	प्रकाशन का स्थान	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर
4.	प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
5.	मुद्रक का नाम	:	सुनील शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
6.	पता प्रेस	:	रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, 22 गोदाम, जयपुर मै. कृष्णा प्रिंटर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, रामनगर, जयपुर पॉपुलर प्रिंटर्स, एम डी रोड, जयपुर हाईटेक प्रिंटर्स, मालवीय नगर, जयपुर
7.	सम्पादक का नाम	:	रजनीश शर्मा
	क्या भारतीय नागरिक है	:	हां
	(यदि विदेशी है तो मूल देश)	:	नहीं
	पता	:	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर

8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं, सुनील शर्मा एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

सुनील शर्मा

सुनी सबके दिल की बात

महिला शक्ति के साथ सार्थक संवाद

**हर कदम में छुपी एक शक्ति,
हर हौसले में एक आस है,
सपनों की उड़ान में पंख लगे,
महिला की दुनिया अब खास है।**

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महिला दिवस (8 मार्च) के उपलक्ष्य पर प्रदेश की आधी आबादी की चुनिंदा महिला प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी अपेक्षाओं और उपलब्धियों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों, राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एवं लखपति दीदी योजना की लाभार्थी महिलाओं, रेडियो जॉकी, टीवी एंकर, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर, महिला खिलाड़ियों, साहित्य, शैक्षणिक, कला जगत, स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा राजनीतिक क्षेत्र में अपनी साख एवं धाक से प्रदेश को गौरवान्वित कर रही महिलाओं से मुख्यमंत्री निवास पर संवाद किया।

महिला सरपंचों को सीख, छोटी-छोटी बातों से पड़ता है बड़ा प्रभाव

मुख्यमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों एवं सरपंचों से संवाद करते हुए कहा कि महिलाओं में मातृत्व का भाव होता है, इसलिए वे किसी भी काम को पूरी संवेदनशीलता के साथ करती हैं। महिला जनप्रतिनिधि अपने-अपने निकाय और ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को बखूबी लागू कर रही हैं। समाज में अन्तिम पायदान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए महिला जनप्रतिनिधियों को अपने स्तर पर जन-जागरण अभियान चलाना चाहिए। साथ ही अपनी ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य करना चाहिए।

महिला सरपंचों ने मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र में किए गए नवाचारों की जानकारी दी और कहा कि वे सरकार की योजनाओं का फायदा आमजन को दिलवाने के लिए आगे भी इसी प्रकार काम करती रहेंगी।

आप मैदान की महारथी, समाज को खेलों में आगे बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने मैदान की महारथी महिला खिलाड़ियों से चर्चा करते हुए आह्वान किया कि खेलों में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटियां समाज को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभाएं। इससे न केवल बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि राजस्थान खेल के क्षेत्र में भी सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। राज्य सरकार प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट के अंतर्गत खेल प्रतिभाओं को आगे लाने और उन्हें उचित मंच प्रदान करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान, हॉस्टल्स, कोचेज आदि सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। स्पोर्ट्स स्कूल और हॉस्टल्स को इंस्टीट्यूट्स से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे खेलने के साथ-साथ पढ़ाई भी सुचारू रूप से हो सके। इस अवसर पर महिला खिलाड़ियों ने सारगर्भित चर्चा करते हुए खेलों के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए।

बदलते परिवेश में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आवश्यक

मुख्यमंत्री ने महिला उद्यमियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। बदलते हुए परिवेश में महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में अनुपयोगी वस्तुओं से दरियां, बर्तन आदि बनाने की परंपरा रही है। यदि इस कौशल को उद्यमिता में शामिल किया जाए, तो अनुपयोगी सामान का निस्तारण होने के साथ ही, महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर महिला उद्यमियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य बजट 2025-26 में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए की गई घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब हमारी मेहनत को पहचान मिलती है तो बहुत खुशी होती है और उत्साहवर्धन होता है।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री ने राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं एवं लखपति दीदी योजना की लाभार्थी महिलाओं से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के लखपति दीदी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। ड्रोन दीदी, पशु सखी और बैंक सखी बनकर महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार ऐसी महिलाओं को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्रुप से जुड़ने के बाद वे अपने पैरों पर तो खड़ी हुई ही हैं, साथ ही उन्हें समाज में नई पहचान भी मिली है। उन्होंने राज्य बजट में राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

नेतृत्वकर्ता पर जनता का विश्वास कायम होना जरूरी

मुख्यमंत्री ने रेडियो जॉकी, टीवी एंकर, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के रूप में काम कर रही महिलाओं से चर्चा के दौरान कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की कही बात का व्यापक असर होता है। मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सुरक्षा मजबूत हुई है। अब हम कामकाजी महिलाओं को रात्रि में बाहर निकलने में असुरक्षा महसूस नहीं होती।

प्रदेश के विकास में मातृशक्ति के योगदान को सम्मान

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइन, अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थानों में मैस भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5 प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए। इसी तरह, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की सोलर दीदी के नए मानदेय कैडर के दिशा-निर्देश, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दिशा-निर्देश, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की नमो ड्रोन दीदी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का विकसित भारत-विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाएं राजनीति, कला, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यो से देश और प्रदेश को गौरवान्वित कर रही हैं। समारोह में श्री शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग महिला खिलाड़ी मानिनी कौशिक तथा पर्वतारोही आशा को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए .मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे एक लाख रुपये के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये करने की घोषणा की।

शक्ति वंदन : भारत के स्व का अभिनंदन

जवाहर कला केन्द्र में शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सशक्त और विकसित देश-प्रदेश बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधी आबादी की भागीदारी के बिना विकास की यात्रा अधूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी शक्ति के लिए मां दुर्गा, धन के लिए मां लक्ष्मी और बुद्धि के लिए मां सरस्वती की उपासना करने की परम्परा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि यह शक्ति वंदन महोत्सव हमारे महिला सशक्तीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और सामाजिक उत्थान के लिए तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। हम राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शक्ति वंदन पुस्तक में उद्यमी महिलाओं के लिए संदेश लिखा। श्री शर्मा ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित देवी अहिल्याबाई होल्कर प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और प्रदर्शनी के रिड्यूस, रीयूज और रीसायकिल आधारित उत्पादों की सराहना की।

एवीजीसी—एक्सआर नीति: डिजिटल क्रांति की ओर महत्वपूर्ण कदम

- **आशीष खण्डेलवाल,** उप निदेशक

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अब डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई एवीजीसी—एक्सआर नीति (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की दृष्टि भी रखती है।

नीति का उद्देश्य और महत्व

एवीजीसी—एक्सआर नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी) जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी बनाना है। यह नीति राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, निवेश आकर्षित करने और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर एवीजीसी—एक्सआर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और भारत भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार का यह कदम समय की मांग के अनुरूप है।

नीति की प्रमुख विशेषताएं

इस नीति के तहत कई आकर्षक प्रावधान शामिल किए गए हैं। राज्य सरकार स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, कर छूट और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा, राज्य में एवीजीसी—एक्सआर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना है, जो प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार का केंद्र होगा। नीति में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है, ताकि वे इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार सकें।

गेमिंग और एनिमेशन उद्योग के लिए विशेष इन्क्यूबेशन सेंटर, तकनीकी पार्क और सह-कार्यस्थल (को-वर्किंग स्पेस) भी बनाए जाएंगे। साथ ही, नीति में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करने की रणनीति शामिल है, जिससे स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच मिल सके।

रोजगार और आर्थिक प्रभाव

एवीजीसी—एक्सआर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह उद्योग अगले कुछ वर्षों में भारत में लाखों नौकरियां पैदा कर सकता है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि इस नीति के जरिए राज्य में 50 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हों। यह न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, यह नीति पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, एक्सटेंडेड रियलिटी का उपयोग कर राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों को डिजिटल रूप से रिक्रिएट किया जा सकता है, जिससे पर्यटकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा।

राजस्थान की एवीजीसी—एक्सआर नीति एक दूरदर्शी कदम है, जो राज्य को डिजिटल युग में अग्रणी बनाने की क्षमता रखता है। यह नीति न केवल आर्थिक विकास को गति देगी, बल्कि युवाओं को अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने का मंच भी प्रदान करेगी।

समीक्षा, निर्देश और समझौते

परस्पर सामंजस्य और सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत् मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने एमओयू किया हैं, उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को देश का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

राज्य सरकार गौरवशाली विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हमारी प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य सरकार इस गौरवशाली विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे आस्था स्थलों का संरक्षण कर हम पर्यटन क्षेत्र को भी विकसित कर सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। बैठक में उन्होंने विकसित होने वाले कन्वेंशन सेन्टर, एग्जीबिशन सेन्टर, मीटिंग हॉल एवं आगन्तुकों के लिए पार्किंग सुविधाओं को विकसित किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

राजस्थान मंडपम में हो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान मंडपम में हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की पुख्ता कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि यहां पर छोटे से लेकर बड़े प्रकार के आयोजन सुगमता से हो सके। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास के साथ विरासत भी' के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मण्डपम में प्रदेश के हैरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाए, जिससे यह स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आकर्षण केन्द्र भी हो एवं यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय भी बन सके।

आरवीयूएनएल और सिंगरेनी कोलियरीज के मध्य एमओयू

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एंव राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य आयोजित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह एमओयू प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में सुदृढ़ प्रसारण तंत्र एवं थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों से राजस्थान जल्द ही देश में 'ऊर्जादाता' की भूमिका में उभरेगा।

कार्मिक, पेंशनर्स को एक क्लिक पर मिलेगी जीपीएफ और बीमा खातों की जानकारी

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार द्वारा सूचना तकनीक एवं अन्य नवाचारों द्वारा जन-सुविधाओं को सुलभ करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। हाल ही में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा विकसित चैटबॉट इस कड़ी में महत्वपूर्ण पहल है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को जीपीएफ और राज्य बीमा खातों की जानकारी अब एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। नवाचार राज्य के लाखों कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए ऋण आदि की सुविधा में सहूलियत देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

विकसित किये गए एआई आधारित चैटबॉट के माध्यम से एसआईपीएफ मोबाइल एप, वेबसाइट एवं पोर्टल पर हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में राज्य कार्मिक उनके राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना के तहत ऋण एवं आहरण की पात्रता, खाते में जमा राशि, मनोनीत व्यक्ति की जानकारी आसानी से तथा किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवाल चैटबॉट पर उपलब्ध होंगे।

फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में अव्वल

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 81 प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जिसके तहत प्रदेश के 73 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। हाल ही में राजस्व तथा उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को योजनाबद्ध रूप से कार्य कर फार्मर रजिस्ट्री के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए सीमाज्ञान के लिए संचालित ई-धरती पोर्टल में आवश्यक संशोधन कर, इसे और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए गए।

सर्कुलर इकोनॉमी : पर्यावरण संकट से बचाव की नई राह

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3 आर और सर्कुलर इकॉनोमी फोरम का आयोजन

जयपुर के राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत् विकास के लक्ष्यों, कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसायटियों को आकार देने, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 3 आर (रिड्यूस, रीयूज व रीसाइकल) और सर्कुलेरिटी इकॉनोमी को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय सर्कुलर इकॉनोमी फोरम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सर्कुलर इकॉनोमी फोरम के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकॉनोमी अत्यन्त प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने ग्रीन बजट पेश कर 27 हजार 854 करोड़ रुपये ग्रीन परियोजना के लिए निर्धारित किए हैं। राजस्थान में 250 करोड़ रुपये से सर्कुलर इकॉनोमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सर्कुलर इकॉनॉमिक इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी, जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। यूनाइटेड नेशन्स सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट द्वारा शुरू किए गए क्षेत्रीय 3 आर और सर्कुलर इकॉनोमी फोरम में CITIIS 2.0 के तहत शहरों और राज्यों के साथ 1800 करोड़ रुपये से अधिक के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

मेल-मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही, पिछले दिनों अपने दिल्ली प्रवास के दौरान लोकसभाध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं केमिकल और फर्टिलाईजर मंत्री श्री जे.पी.नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर.पाटिल से मुलाकात कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की।

त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा

छाया एवं आलेख : **रा. सुजस**

राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा ग्राम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की सघन हरियाली की गोद में उमराई के छोटे से ग्राम स्थित माताबाड़ी में प्रतिष्ठित हैं मां त्रिपुरा सुंदरी।

कहा जाता है कि मंदिर के आस-पास कभी तीन दुर्ग शक्तिपुरी, शिवपुरी तथा विष्णुपुरी थे। इन तीन दुर्गों में अवस्थित होने के कारण देवी का नाम त्रिपुरा सुन्दरी पड़ा। भक्तों का यह भी मानना है कि प्रातःकालीन बेला में कुमारिका, मध्यान्ह में यौवना और बेला सायंकाल में प्रौढ़ रूप में मां के दर्शन होते हैं। इसी कारण माता को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठों में शामिल हैं। मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति अष्टदश यानी अठारह भुजाओं वाली है। मूर्ति में माता दुर्गा के नौ रूपों की प्रतिकृतियां अंकित हैं। देवी मां सिंह, मयूर और कमल आसन पर विराजमान हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में सपरिवार विधि-विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के स्थापना दिवस को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब से राजस्थान दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय हिंदू पंचांग (विक्रम सम्वत) के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के साथ ही राजस्थान दिवस अब भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अधिक निकट आ गया है। राज्य का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। तब सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से विभिन्न रियासतों का विलय कर इसे वृहद राजस्थान के रूप में गठित किया गया था। वृहद राजस्थान के गठन की प्रक्रिया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूर्ण हुई थी। इस तिथि को ध्यान में रखते हुए अब से हर वर्ष राजस्थान दिवस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि हर वर्ष अंग्रेजी कलेण्डर की अलग दिनांक को आती है।

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक — सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त, सुनील शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
संपादक— डॉ. रजनीश शर्मा, मैसर्स पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर से मुद्रित (25,000 प्रतियां), ' राजस्थान सुजस ' - पृष्ठ संख्या 60, मूल्य 1.00 रुपये • अंक प्रतियां 76,000